राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

# स्वतंत्र प्रभात

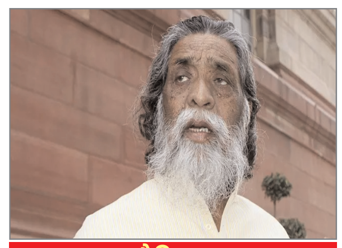

स्वतंत्र प्रभात दैनिक अख़बार तथा ऑनलाइन चैनल से सीधा जुड़ने के लिए संपर्क करें........ 9511151254

@swatantraprabhatmedia | @swatantramedia | RNI.No. UHIN/2012/43078 (epaper.swatantraprabhat.com ) | @SwatantraPrabhatonline | news@swatantraprabhat.com

सीतापुर से प्रकाशित एंव अयोध्या ,प्रयागराज ,मिर्जापर ,गोरखपुर , बरेली ,बुंदेलखंड , उत्तराखंड , देहरादून

सीतापुर, सोमवार , 09 मार्च 2026

वर्ष 14, अंक 316, पृष्ट 04, मूल्य: 01 रुपया

www.swatantraprabhat.com

गाज़ियाबाद , दिल्ली , हरियाणा , चंडीगढ़ , झारखण्ड , बिहार , मध्य प्रदेश ,असम, तेलंगाना आदि जनपदो में प्रसारित

बीडीएस की पढ़ाई पूरी कर डेंटल सर्जन बने शिवांक द्विवेदी...03

केवल वादे या वास्तविक विकास! जिले के दुल्लभछड़ा में केंद्रीय विद्यालय और मॉडल डिग्री कॉलेज अभी भी अधर में...04

## वॉशरूम में पानी नहीं, रास्ते पर कचरा... राष्ट्रपति मुर्मू के 'अपमान' पर बुरी फंसी ममता सरकार, एक्शन में गृह मंत्रालय

**स्वतंत्र प्रभात संवाददाता**

पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यक्रम के दौरान कथित रूप से प्रोटोकॉल में हुई लापरवाही को लेकर केंद्र सरकार ने कड़ा रुख अपना लिया है. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पूरे मामले पर राज्य सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है. सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव से आज शाम तक इस मामले में पूरी जानकारी देने को कहा है. रिपोर्ट में राष्ट्रपति के दौरे के दौरान किए गए प्रोटोकॉल, कार्यक्रम स्थल, यात्रा मार्ग और अन्य व्यवस्थाओं से जुड़े सभी पहलुओं पर जवाब मांगा गया है।

सूत्रों के अनुसार, राष्ट्रपति की सुरक्षा से जुड़े 'ब्लू बुक' नियमों के मुताबिक कई स्तरों पर प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ है. केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से चार प्रमुख बिंदुओं पर स्पष्टीकरण मांगा है, जिनमें शामिल हैं:

**राष्ट्रपति प्रोटोकॉल का पालन**

कार्यक्रम स्थल की व्यवस्था

राष्ट्रपति के काफिले का मार्ग

सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाएं

सूत्रों के मुताबिक, कई गंभीर सवाल उठाए गए हैं. इनमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि राष्ट्रपति के स्वागत और विदाई के समय राज्य के शीर्ष अधिकारी मौजूद क्यों नहीं थे. आम तौर पर राष्ट्रपति के दौरे के दौरान मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और डीजीपी की मौजूदगी अपेक्षित होती है. लेकिन इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति का स्वागत

और विदाई केवल सिलीगुड़ी के मेयर ने किया।

**वॉशरूम में पानी नहीं, रास्ते पर बिखरा कचरा**

इसके अलावा यह भी आरोप है कि कार्यक्रम स्थल पर राष्ट्रपति के लिए बनाए गए वॉशरूम में पानी तक उपलब्ध नहीं था. वहीं जिस मार्ग से राष्ट्रपति का काफिला गुजरा, वहां साफ-सफाई की स्थिति भी खराब बताई जा रही है और रास्ते में कचरा होने की शिकायत सामने आई है. सूत्रों का कहना है कि इन परिस्थितियों के लिए दार्जिलिंग के जिलाधिकारी, सिलीगुड़ी पुलिस कमिश्नरेट के पुलिस आयुक्त और अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को जिम्मेदार माना जा रहा है।

**राष्ट्रपति के कार्यक्रम पर ममता बनर्जी का जवाब**

इस विवाद के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि सिलीगुड़ी में आयोजित कार्यक्रम किसी सरकारी आयोजन का हिस्सा नहीं था, बल्कि यह इंटरनेशनल संथाल काउंसिल नामक एक निजी संस्था द्वारा आयोजित 'इंटरनेशनल आदिवासी संथाल सम्मेलन' था, जिसमें राष्ट्रपति को आमंत्रित किया गया था।

मुख्यमंत्री के मुताबिक जिला प्रशासन ने पहले ही राष्ट्रपति सचिवालय को लिखित और मौखिक रूप से बताया था कि कार्यक्रम स्थल पर पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं हैं. इसके बावजूद कार्यक्रम तय समय पर आयोजित किया गया।

ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि राष्ट्रपति के स्वागत और विदाई के लिए जो प्रोटोकॉल सूची राष्ट्रपति सचिवालय की ओर से तय की गई थी, उसी के अनुसार सिलीगुड़ी नगर निगम के मेयर, दार्जिलिंग के डीएम और सिलीगुड़ी पुलिस आयुक्त मौजूद थे. उन्होंने दावा किया कि राज्य सरकार की ओर से किसी भी तरह का प्रोटोकॉल उल्लंघन नहीं हुआ।

**राष्ट्रपति ने जताई थी नाराजगी**

इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी कार्यक्रम के दौरान व्यवस्थाओं पर नाराजगी जताई थी. उन्होंने सवाल उठाया था कि आमतौर पर राष्ट्रपति के दौरे के समय मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री स्वागत के लिए मौजूद रहते हैं, लेकिन इस कार्यक्रम में ऐसा नहीं हुआ. राष्ट्रपति ने कार्यक्रम स्थल को लेकर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि कार्यक्रम ऐसे स्थान पर रखा गया जहां लोगों के लिए पहुंचना मुश्किल था।

**प्रधानमंत्री मोदी ने भी जताई नाराजगी**

इस मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने इसे 'शर्मनाक और अभूतपूर्व' बताया. प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति ने जो पीड़ा व्यक्त की है, उससे देश के लोगों को गहरा दुख हुआ है. उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्रपति का पद राजनीति से ऊपर है और इसकी गरिमा का सम्मान किया जाना चाहिए।

**तृणमूल कांग्रेस का पलटवार**

वहीं सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल के खिलाफ पूरे केंद्रीय तंत्र का इस्तेमाल किया जा रहा है. पश्चिम बंगाल में अगले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. ऐसे में इस मुद्दे को लेकर राज्य की सियासत भी तेज हो गई है और सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और विपक्षी बीजेपी के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है. अब सभी की नजर उस रिपोर्ट पर टिकी है जो पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव गृह मंत्रालय को सौंपेंगे. माना जा रहा है कि रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार आगे की कार्रवाई तय कर सकती है।

## सुप्रीम कोर्ट की महिला वकीलों को जज बनाने पर करें विचार... H C कॉलेजियम से बोले CJI

**स्वतंत्र प्रभात संवाददाता**

भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने रविवार को ज्यूडिशियरी में और ज्यादा इंस्टीट्यूशनल सुधारों की वकालत की ताकि ज्यादा महिलाओं को कानूनी फील्ड में लाया जा सके और कहा कि हाई कोर्ट कॉलेजियम को काबिल महिला सदस्यों को जज बनाने पर एक नियम के तौर पर विचार करना चाहिए, न कि किसी अपवाद के तौर पर. एक कार्यक्रम में बोलते हुए, भारत के चीफ जस्टिस ने इस बात पर जोर दिया कि बार के सदस्यों को एक सीधी सी सच्चाई को मानना चाहिए. महिला सदस्य कोई रियायत नहीं मांग रही हैं. वे सही और उचित रिप्रेजेंटेशन चाहती हैं, जिसकी बहुत पहले से जरूरत थी. जब प्रोफेशन खुद इस सच्चाई को समझेगा, तभी बेंच तक का रास्ता साफ होगा।

उन्होंने इंडियन वीमेन इन लॉ के पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस में महिला वकीलों और ज्यूडिशियरी के सदस्यों की तालियों के बीच कहा, जिसका टॉपिक था 'हाफ द नेशन हाफ द बेंच ब्रिज द गैप बैलेंस द बेंच. '

CJI ने हाई कोर्ट कॉलेजियम से आग्रह किया कि वे अपने विचार का दायरा बढ़ाएं और अपने राज्यों की उन महिला वकीलों को शामिल करें जो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रही हैं।

महिलाओं को लेकर CJI ने कही ये बात

CJI सूर्यकांत ने कहा कि अगर प्रोग्रेस को सार्थक बनाना है, तो इसे इंस्टीट्यूशनल बनाना होगा., कहानी यह नहीं होनी चाहिए

कि किसी एक व्यक्ति को ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन मिला, बल्कि यह होनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट और देश भर के हाई कोर्ट ने जानबूझकर अपने प्रोसेस में फेयरनेस को शामिल किया।

CJI सूर्यकांत ने आगे कहा कि जब ऐसा होगा, तो रिप्रेजेंटेशन अब पर्सनैलिटी या पक्के इरादे के पलों पर निर्भर नहीं रहेगा, यह इंस्टीट्यूशन के स्ट्रक्चर में ही टिका रहेगा, और आखिरकार, इसी तरह से लंबे समय तक चलने वाला बदलाव आता है. उन्होंने कहा कि सुधार का एक एरिया हाई कोर्ट कॉलेजियम के अंदर है और उन्हें यह समझना होगा कि सोच-समझकर कार्रवाई करने का समय भविष्य में नहीं, बल्कि अभी है।

**महिला वकीलों को जज बनाने की अपील**

उन्होंने कहा कि जहां बार की सही, काबिल महिला सदस्य उपलब्ध हैं, उन पर विचार करना कोई अपवाद नहीं होना चाहिए; यह नॉर्म होना चाहिए और जहां, कुछ हाई कोर्ट या जिलों में, एक खास उम्र के दायरे में सही कैंडिडेट तुरंत उपलब्ध नहीं हैं, तो यह रुकावट नहीं बननी चाहिए. उन्होंने कहा, 'मैं हाई कोर्ट कॉलेजियम से रिक्वेस्ट करता हूं कि वे अपने विचार का दायरा बढ़ाएं और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाली उन महिला वकीलों को भी शामिल करें जो उस राज्य से हैं। 'इंडियन वीमेन इन लॉ' ऑर्गनाइजेशन से जुड़ी सीनियर वकील शोभा गुप्ता और महालक्ष्मी पावनी ने मेहमानों का स्वागत किया. इनमें पूर्व CJI एनवी रमना और सुप्रीम कोर्ट के दूसरे मौजूदा जज शामिल थे, जिनमें जस्टिस बीवी नागरत्ना और उज्जल भुयान शामिल थे. CJI ने बताया कि अभी कई महिलाएं अलग-अलग हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस के तौर पर काम कर रही हैं, और पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में 18 मौजूदा महिला जज हैं. उन्होंने कहा कि इसी तरह, मद्रास और बॉम्बे हाई कोर्ट में भी लगभग एक दर्जन महिला जज हैं. CJI सूर्यकांत ने बताया कि डिस्ट्रिक्ट ज्यूडिशियरी में भी अच्छी स्थिति है, जो शायद आगे क्या होने वाला है, इसका सबसे साफ इशारा है. उन्होंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ज्यूडिशियल ऑफिसर्स की वर्किंग स्ट्रेंथ में लगभग 36.3 परसेंट महिलाएं होने से, फाउंडेशन लगातार मजबूत हो रहा है।

## संक्षिप्त ख़बरें

### मुजफ्फरनगर में पकड़ा गया हनी ट्रैप गैंग, प्रधानी चुनाव के कैंडिडेट्स को बनाते थे निशाना... ऐसे ऐंठते थे पैसे

हनी ट्रैप गैंग के मामले तो आपने बहुत से सुने होंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश के भंदरअसल, शनिवार को एक व्यक्ति ने नई मंडी कोतवाली में लिखित तहरीर देकर ये आरोप लगाया गया कि क्षेत्र के आफताब, रियासत, परवेज, साजिद और वरजिना नाम की महिला ने एक हनी ट्रैप का गैंग बनाया हुआ है, जो भोले-भाले लोगों को अपने चंगुल में फंसा कर उनसे मोटी रकम ऐंठने का काम करता है. पुलिस ने तुरंत इस मामले में बीएनएस की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी।

**हनी ट्रैप गैंग का भंडाफोड़**

शुरूआती जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने इस गैंग के चार 4 सदस्य आफताब, रियासत, साजिद और वरजीना को गिरफ्तार कर जेल भेजने का काम किया है. इस गैंग का एक सदस्य परवेज भी पुलिस को गिरफ्त से बाहर है, जिसकी तलाश जारी है. पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपियों ने बताया कि वह अधिकतर प्रधानी चुनाव में खड़े हुए उम्मीदवार को अपनी साजिश में फंसाते थे. जिसके बाद थाने में झूठा मुकदमा छेड़छाड़ और दुष्कर्म का दर्ज कराकर या तो चुनाव में उस पीड़ित उम्मीदवार को बैठने का दबाव बनाते थे या फिर उससे मोटी रकम ऐंठ लिया करते थे।

**एक महिला सहित चार लोग अरेस्ट**

इसके अलावा भी इस गैंग ने कई लोगों को अपना शिकार बनाया है, जिसके चलते मुजफ्फरनगर और हरिद्वार में इस गैंग पर कई मुकदमे दर्ज हैं. इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए मुजफ्फरनगर एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने बताया कि हनी ट्रैप का एक मामला जांच से पकड़ा गया है, जिसमें एक महिला सहित चार लोग गिरफ्तार किए गए हैं. गिरफ्तार आरोपी तीन आरोपी रथेडी केर रहने वाले हैं, जबकि महिला नई मंडी सरवट इलाके की रहने वाली है।

**फरार आरोपी की तलाश में पुलिस**

रियासत नाम का एक आरोपी फरार चल रहा है, जो कि गिरफ्तार महिला का सगा भाई बताया जा रहा है. ये लोग प्रधानी चुनाव कैंडिडेट या फिर पैसे वाले लोगों को अपना शिकार बनाते थे. उन्हें हनी ट्रैप में फंसाकर झूठे केस में फंसाते थे और फिर समझौते के नाम पर पैसे ऐंठे जाते थे. दो मामले ऐसे संज्ञान में आए हैं, उनमें स्नद्धक्र भी दर्ज की गई हैं. अब तक 10 से 15 लाख रुपए ऐंठने की बात की पुष्टि हुई है।

## अल-फलाह के चेयरमैन जावेद सिद्दीकी को जमानत, ईडी ने किया विरोध, कोर्ट ने बताई वजह

**स्वतंत्र प्रभात संवाददाता**

दिल्ली कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अल-फलाह ग्रुप के चेयरमैन जावेद सिद्दीकी को दो हफ्ते की अंतरिम जमानत दे दी है. कोर्ट की तरफ से यह राहत इसलिए दी गई है, ताकि वह अपनी पत्नी की देखभाल कर सकें. जो स्टेज-4 ओवेरियन कैंसर का इलाज करा रही हैं. जस्टिस शीतल चौधरी की बेंच ने ये फैसला सुनाया है. कोर्ट ने शनिवार को यह आदेश देते हुए कहा कि सिद्दीकी की पत्नी कीमोथेरेपी से गुजर रही हैं. इस दौरान उन्हें देखभाल और सहारे की जरूरत है. अदालत ने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए आरोपी को अंतरिम जमानत देना उचित है. कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी बताया कि सिद्दीकी की पत्नी दिल्ली के एक अस्पताल में कीमोथेरेपी करवा रही हैं. इस संबंध में पेश किए गए मेडिकल दस्तावेजों पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कोई आपत्ति नहीं जताई.

**बच्चे नहीं आ सकते इस समय भारत**

कोर्ट ने यह भी कहा कि दंपति के तीनों बच्चे यूएई में पढ़ाई कर रहे हैं और फिलहाल भारत नहीं आ सकते हैं. ऐसे में महिला के पास परिवार का कोई और सदस्य मौजूद नहीं है, इसलिए पति के तौर पर सिद्दीकी का उनके पास होना जरूरी है. यही वजह है कि उन्हें जमानत दी गई है.

**क्या है पूरा मामला?**

जावेद सिद्दीकी को प्रवर्तन निदेशालय ने 18 नवंबर 2025 को धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत दर्ज मामले में गिरफ्तार किया था. यह मामला अल-फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों से कथित धोखाधड़ी से जुड़ा है. अदालत ने सिद्दीकी को एक-एक लाख रुपये के निजी मुचलके और जमानतदार पर दो सप्ताह की अंतरिम जमानत दी है.

**ईडी ने किया जमानत का विरोध**

ईडी ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि सिद्दीकी गंभीर अपराधों में शामिल हैं. जमानत के दौरान वह जांच को प्रभावित कर सकते हैं. हालांकि अदालत ने कहा कि आरोपी अब तक जांच में सहयोग कर रहा है और फरार होने की कोई कोशिश नहीं की है.

## कोडीन युक्त कफ सिरप की तस्करी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़, 8 आरोपी गिरफ्तार

**स्वतंत्र प्रभात संवाददाता**

**गाजियाबाद-** गाजियाबाद पुलिस ने नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए कोडीन युक्त कफ सिरप की तस्करी करने वाले एक अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस मामले में करीब 13 करोड़ रुपये से अधिक की चल-अचल संपत्ति को सीज कर दिया है। पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद के निर्देश पर क्राइम ब्रांच, स्वॉट टीम और नंदग्राम थाना पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर गिरोह के आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार आरोपियों में सहारनपुर निवासी विभोर राणा और विशाल सिंह भी शामिल हैं।

**ट्रकों से बरामद हुआ भारी मात्रा में कफ सिरप**

पुलिस जांच में चार ट्रकों से चूने के बोरों के बीच छिपाकर रखी गई 1150 पेटियों में करीब 15 लाख 73 हजार से अधिक Eskuf और Phensedyl कफ सिरप की शीशियां बरामद की गईं। इनकी बाजार कीमत करीब 3 करोड़ 40 लाख रुपये बताई जा रही है।

**नकदी, कार और दस्तावेज भी जब्त**

पुलिस ने कार्रवाई के दौरान एक Hyundai Creta कार, करीब 20 लाख रुपये नकद, लैपटॉप, मोबाइल फोन और कई अहम दस्तावेज भी बरामद किए हैं।

**फर्जी कंपनियों के जरिए चल रहा था कारोबार**

जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी फर्जी कंपनियों के नाम पर कफ सिरप की तस्करी कर रहे थे और इसी अवैध कारोबार से करोड़ों की संपत्ति बना ली थी। पुलिस ने NDPS Act के तहत कार्रवाई करते हुए करीब 12 करोड़ 55 लाख रुपये की चल-अचल संपत्ति को फ्रीज कर दिया है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक गिरोह के नेटवर्क और अन्य आरोपियों की तलाश के लिए जांच जारी है।

## चर्चित नासिर-जुनैद हत्याकांड मामले में मोनू मानेसर को मिली जमानत, राजस्थान H C से सशर्त रिहाई के बाद पहुंचा घर

**स्वतंत्र प्रभात संवाददाता**

**बादशाहपुर (गुरुग्राम)।** बहुचर्चित नासिर-जुनैद हत्याकांड में राजस्थान उच्च न्यायालय से जमानत मिलने के बाद आरोपित मोहित यादव उर्फ मोनू मानेसर शनिवार को घर पहुंच गया। पांच मार्च को उच्च न्यायालय ने सशर्त जमानत देते हुए आदेश दिया कि हर तीन महीने पर राजस्थान के भरतपुर जिले के गोपालगढ़ थाने में हाजिरी लगानी होगी। जमानत की कागजी कार्यवाही पूरी होने के बाद शनिवार देर शाम मोनू को भरतपुर जेल से रिहा किया गया। राजस्थान पुलिस ने सुरक्षा देकर उसे हरियाणा सीमा तक पहुंचाया।

**फरवरी 2023 में गाड़ी से मिले थे कंकाल**

भिवानी में 16 फरवरी 2023 को बोलेरो गाड़ी में दो कंकाल मिले थे। गाड़ी पूरी तरह जली हुई थी। दोनों कंकालों की पहचान राजस्थान के भरतपुर जिले के गांव घाटमिका निवासी 28 वर्षीय नासिर एवं 33 वर्षीय जुनैद के रूप में की गई थी। दोनों के स्वजन ने मोनू मानेसर व उसके साथियों पर मारपीट कर भरतपुर की पहाड़ी से किडनैप करने व बाद में जिंदा जलाने का आरोप लगाया था। राजस्थान पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। तब से मोनू जेल में बंद था। पिछले साल 31 जनवरी को भी जमानत याचिका लगाई गई थी लेकिन उच्च न्यायालय ने खारिज कर दी थी। कुछ दिन पहले दोबारा फिर जमानत की अर्जी लगाई गई। सुनवाई के दौरान मोनू के अधिवक्ताओं ने दलील दी कि उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है।

**दो मामलों में हो चुका है बरी**

सह-आरोपित अनिल कुमार को सर्वोच्च न्यायालय 28 जनवरी को जमानत दे चुका है। मोनू के विरुद्ध तीन आपराधिक मामले जरूर दर्ज हैं लेकिन उनमें से दो में वह बरी हो चुका है। एक मामले में उसे पहले से जमानत मिल चुकी है। जिला बार एसोसिएशन गुरुग्राम के पूर्व अध्यक्ष कुलभूषण भारद्वाज ने बताया कि हाई कोर्ट में यह भी तर्क दिया गया कि आरोपित सात अक्टूबर 2023 से जेल में बंद है। अब तक मामले में 74 गवाहों में से एक भी गवाह की गवाही नहीं हो सकी है। इससे स्पष्ट है कि ट्रायल जल्द पूरा होने की संभावना नहीं है। राजस्थान सरकार की ओर से लोक अभियोजक और शिकायतकर्ता पक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ता ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि मामला गंभीर प्रकृति का है। उपलब्ध साक्ष्यों को देखते हुए आरोपित को जमानत नहीं दी जानी चाहिए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने कहा कि सह-आरोपित को पहले ही सर्वोच्च न्यायालय से जमानत मिल चुकी है और अब तक एक भी गवाह का बयान दर्ज नहीं हुआ है।

**जिले में गोरक्षक की पहचान**

न्यायालय ने आदेश दिया कि मोहित यादव उर्फ मोनू मानेसर को एक लाख रुपये के निजी मुचलके और 50-50 हजार रुपये के दो जमानतदारों पर रिहा किया जाए। साथ ही उसे हर तीन महीने में संबंधित पुलिस थाने में अपनी हाजिरी दर्ज करानी होगी। बता दें कि मोनू मानेसर की जिले में गोरक्षक की पहचान है। विश्व हिंदू परिषद के गुरुग्राम विभाग मंत्री देवेंद्र सिंह का कहना है कि मोनू मानेसर व टीम की सक्रियता की वजह से जिले में ही नहीं बल्कि आसपास के इलाकों में गो-तस्करी के ऊपर लगाम लग गई थी। इस वजह से मोनू सहित पूरी टीम को निशाना बनाया गया।

## गुजरात में सत्ता नहीं, व्यवस्था बदलने की जरूरत... गांधीनगर में BJP सरकार पर गरजे केजरीवाल

**स्वतंत्र प्रभात संवाददाता**

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल रविवार को गुजरात में परिवर्तन लाओ, किसान बचाओ यात्रा रैली कर भाजपा और कांग्रेस पर जमकर हमले किए. गांधी नगर में आयोजित रैली में उन्होंने गुजरात की जनता से 30 साल से राज कर रही भाजपा को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि इस बार गुजरात में जनता की सरकार बनेगी और अपने फैसले खुद लेगी. उन्होंने जोर दिया कि हमें सिर्फ पार्टी नहीं बदलनी है, बल्कि गुजरात की तरक्की के लिए पूरी व्यवस्था बदलनी है. अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पिछले 10-12 दिनों से यशु भाई, प्रवीण राम और मनोज सोरठिया ने भगवान सोमनाथ के दर्शन कर गांव-गांव और मोहल्ले-मोहल्ले से होते हुए गांधीनगर तक किसान यात्रा निकाली है. इस यात्रा के दौरान वे हजारों किसानों से मिले और पाया कि हर जगह गुजरात का किसान दुखी है और खून के आंसू रो रहा है. कहीं पीने का पानी नहीं है, कहीं सिंचाई का पानी नहीं है, हर चीज के दाम बढ़ गए हैं और किसानों को अपनी फसल के पूरे दाम भी नहीं मिल रहे हैं।

**गुजरात में किसानों का बुरा हाल**

बोटाद की घटना का जिक्र करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कुछ दिन पहले वहां किसान करदा प्रथा के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे और कोई हिंसा नहीं कर रहे थे. लेकिन भाजपा की अत्याचारी सरकार ने किसानों के घरों में घुसकर उन्हें घसीटा, उनका अपमान किया और जेल में डाल दिया. किसानों की पत्नियां, माताएं और बच्चे बहुत रोए, लेकिन भाजपा सरकार नहीं मानी और 85 किसानों को कई महीनों तक जेल में रखा. जब आम लोग दिवाली मना रहे थे, तब किसान भाई जेल के अंदर तड़प रहे थे और उनके परिवार रो रहे थे. अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यह बात केवल 85 किसानों की नहीं है, बल्कि इसके जरिए भाजपा पूरे गुजरात के किसानों को संदेश देना चाहती है कि खबरदार किसी ने आवाज उठाई तो उसका भी यही हाल किया जाएगा. उन्होंने जनता से पूछा कि क्या वे इस अत्याचार को बर्दाश्त करेंगे या इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे. भाजपा खुलेआम किसानों की बेइज्जती और उनका अपमान कर रही है. इस बार हर चुनाव में हर किसान को कसम खानी है कि किसी को भी वोट दे देंगे, लेकिन भाजपा को वोट नहीं देंगे. गुजरात से कमल को उखाड़ कर फेंक देना है, कमल को बिल्कुल वोट नहीं देनी है और हर किसान को इस बार यह कसम खानी है. अरविंद केजरीवाल ने सवाल किया कि चैतर वसावा का क्या कसूर है? नरेगा में भारी भ्रष्टाचार है, ये लोग जनता का पैसा खा जाते हैं, फर्जी किताबों में कुछ भी लिख देते हैं और लोगों के नाम का पैसा चोरी कर लेते हैं. चैतर वसावा ने लोगों की आवाज उठाई थी. इसलिए उसे पकड़ कर जेल में डाल दिया गया. प्रवीण राम ने किसानों की आवाज उठाई तो उसे भी पकड़ कर जेल

में डाल दिया गया. इन्होंने मुझे भी नहीं छोड़ा और पकड़ कर जेल में डाल दिया. भारत के 75 साल के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि दिल्ली के एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को 6 महीने तक जेल में रखा गया हो।

**दिल्ली में भी पहले गुजरात जैसा ही हाल था**

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पहले दिल्ली में गुजरात जैसा ही हाल था. दिल्ली में सिर्फ कांग्रेस और भाजपा दो ही पार्टियां थीं और लोग इनकी मिलीभगत से परेशान हो चुके थे. तब लोगों ने तय किया कि वे इन दोनों पार्टियों को उखाड़ फेंकेंगे और अपनी खुद की सरकार बनाएंगे. 2015 में जनता ने झाडू को वोट देकर अपनी सरकार बनाई और मुझे मुख्यमंत्री बना दिया. अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा कि फिर पंजाब के लोगों ने अकाली दल, कांग्रेस और भाजपा को हराकर आम आदमी की सरकार बनाई और किसान के बेटे भगवंत मान को मुख्यमंत्री बनाया. वहां लोगों की मांग पर खेती की बिजली मुफ्त कर दी गई, जिससे किसान जितनी चाहें बिजली इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके अलावा घर की बिजली भी मुफ्त कर दी गई. अब पंजाब में किसानों को रात के बजाय दिन में लगातार 10 घंटे बिजली मिलती है और हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचा दिया गया है।

**गुजरात में पेपर लीक क्यों हो जाते हैं?**

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि एक गरीब किसान अपनी जमीन और जेवर बेचकर, दिन-रात मेहनत करके पैसे जमा करता है और अपने बच्चे को अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत या राजकोट पढ़ने भेजता है. लेकिन जब बच्चा खूब पढ़ाई करके पेपर देने जाता है तो पेपर लीक हो जाता है. ऐसा कैसे हो जाता है, जबकि मैं 10 साल दिल्ली का मुख्यमंत्री रहा और वहां एक भी पेपर लीक नहीं हुआ और पंजाब में भी 5 साल से हमारी सरकार है, वहां भी एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है. लेकिन गुजरात में रोज पेपर लीक हो जाते हैं. अरविंद केजरीवाल ने कहा ये लोग कहते हैं कि गुजरात में दारूबंदी है. जबकि सरेआम शराब बिकती है और पूरे गुजरात में फोन करने पर शराब की होम डिलीवरी होती है. आज कोई स्कूल या कॉलेज ऐसा नहीं है जहां ड्रग्स न बिक रही हो और यह सब इन्हीं के लोग बेच रहे हैं. अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 2027 के चुनाव में सिर्फ पार्टी नहीं बदलनी, बल्कि पूरी व्यवस्था बदलनी है. अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जब जनता की सरकार बनेगी तो वे सबसे पहले नेताओं का भ्रष्टाचार खत्म करेंगे।

# बिहार की राजनीति में ऐतिहासिक मोड़ : नीतीश कुमार के फैसले से नई पटकथा, पहली बार भाजपा के मुख्यमंत्री की ओर बढ़ता राज्य

बिहार की राजनीति इन दिनों एक ऐसे मोड़ पर खड़ी दिखाई दे रही है, जहाँ से आगे की दिशा पूरी तरह बदलती नजर आ रही है। लगभग दो दशकों से अधिक समय तक राज्य की राजनीति के केंद्र में रहे नीतीश कुमार का राज्यसभा के लिए नामांकन केवल एक राजनीतिक घटना नहीं है, बल्कि यह बिहार के राजनीतिक इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत का संकेत भी माना जा रहा है। लंबे समय से सत्ता की कमान संभालने वाले नेता का यह फैसला बताता है कि राजनीति में समय के साथ बदलाव अनिवार्य होता है और वही नेता इतिहास में सम्मान पाता है जो परिस्थितियों को समझकर सही समय पर निर्णय लेता है। पिछले एक महीने से बिहार की राजनीति में जो घटनाक्रम धीरे-धीरे सामने आ रहा था, उसने अब एक स्पष्ट रूप ले लिया है। राजनीतिक हलकों में यह चर्चा तेज थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब सक्रिय राज्य राजनीति से थोड़ा पीछे हटकर नई भूमिका निभाने की तैयारी कर रहे हैं। इसी दौरान उनके पुत्र निशांत कुमार के राजनीति में सक्रिय होने की चर्चाएं भी तेज हो गई थीं। अब तक सार्वजनिक जीवन से दूर रहने वाले निशांत हाल के दिनों में पार्टी कार्यक्रमों और राजनीतिक बैठकों में दिखाई देने लगे थे। पार्टी के भीतर कई नेता उन्हें संगठन को भविष्य में संभालने वाली नई पीढ़ी के रूप में देखने लगे थे। राजनीतिक रणनीति के स्तर पर यह भी माना जा रहा था कि निशांत कुमार को राज्यसभा भेजकर उन्हें राष्ट्रीय राजनीति का अनुभव दिया जाए। हालांकि बाद में रणनीतिकारों ने यह समझा कि बिहार की राजनीति में ही उनकी सक्रियता अधिक प्रभावी हो सकती है। इसी बीच परिस्थितियां तेजी से बदलीं और राज्यसभा के लिए स्वयं नीतीश कुमार के नामांकन की खबर सामने आई। यह निर्णय केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि गठबंधन की व्यापक रणनीति का हिस्सा भी माना जा रहा है।

बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। उन्होंने ऐसे समय में राज्य की बागडोर संभाली जब बिहार विकास और प्रशासनिक व्यवस्था की चुनौतियों से जूझ रहा था। उनके नेतृत्व में कानून-व्यवस्था को सुधारने, सड़कों और आधारभूत संरचना को मजबूत करने तथा शिक्षा और सामाजिक योजनाओं को विस्तार देने के प्रयास हुए। इसी कारण उन्हें 'सुशासन बाबू' की पहचान मिली। उनकी राजनीति का मूल आधार विकास, सामाजिक संतुलन और प्रशासनिक सुधार रहा है। आज जब वे राज्यसभा की ओर बढ़ रहे हैं तो इसे एक सम्मानजनक और रणनीतिक परिवर्तन के रूप में देखा जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उनके इस कदम से बिहार की राजनीति में एक नई संरचना बनने जा रही है। यह भी कहा जा रहा है कि स्वास्थ्य और परिवार को प्राथमिकता देते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री पद से पीछे हटने का निर्णय लिया है। ऐसा निर्णय लेना आसान नहीं होता, विशेष रूप से तब जब कोई नेता लंबे समय तक सत्ता के केंद्र में रहा हो। इस पूरे घटनाक्रम में एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि बिहार में पहली बार भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता मुख्यमंत्री पद संभाल सकता है। पिछले विधानसभा चुनावों में भाजपा ने उल्लेखनीय प्रदर्शन किया था और वह राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। ऐसे में गठबंधन की राजनीति के तहत यह संभावना मजबूत हुई कि मुख्यमंत्री पद भाजपा के हिस्से में आए। यदि ऐसा होता है तो यह बिहार की राजनीति में एक ऐतिहासिक परिवर्तन माना जाएगा।

हालांकि यह बदलाव केवल सत्ता परिवर्तन नहीं है, बल्कि गठबंधन की नई संरचना का भी संकेत है। सूत्रों के अनुसार नई सरकार के गठन के समय मंत्रिमंडल का संतुलन इस तरह रखा जाएगा कि सभी सहयोगी दलों को प्रतिनिधित्व मिल सके। भाजपा और जदयू दोनों के मंत्रियों की संख्या लगभग बराबर रहने की संभावना है। इसके साथ ही अन्य सहयोगी दलों को भी मंत्रिमंडल में स्थान दिया जा सकता है।

राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो यह परिवर्तन राष्ट्रीय राजनीति पर भी प्रभाव डाल सकता है। इस वर्ष देश के कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे समय में बिहार में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार का गठन पार्टी के लिए सकारात्मक संदेश दे सकता है। यदि भाजपा पहली बार बिहार में मुख्यमंत्री पद संभालती है तो यह उसके संगठनात्मक विस्तार और राजनीतिक प्रभाव को और मजबूत करेगा।

दूसरी ओर जदयू के लिए भी यह बदलाव एक नई भूमिका तय कर सकता है। नीतीश कुमार राष्ट्रीय स्तर पर अधिक सक्रिय होकर पार्टी की रणनीति और गठबंधन की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उनके लंबे अनुभव और संतुलित नेतृत्व शैली का लाभ राष्ट्रीय राजनीति में भी मिल सकता है। यही कारण है कि कई राजनीतिक विश्लेषक इसे केवल बिहार तक सीमित परिवर्तन नहीं बल्कि व्यापक राजनीतिक रणनीति का हिस्सा मान रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम में यह भी उल्लेखनीय है कि सत्ता परिवर्तन के बावजूद गठबंधन की एकता बनाए रखने की कोशिश की जा रही है। भाजपा और जदयू दोनों ही दल चाहते हैं कि सरकार स्थिर और मजबूत बने ताकि विकास की गति बनी रहे। बिहार जैसे बड़े और महत्वपूर्ण राज्य में राजनीतिक स्थिरता अत्यंत आवश्यक मानी जाती है।

राजनीतिक इतिहास में कई बार ऐसा देखा गया है कि एक युग समाप्त होने के साथ ही दूसरा युग प्रारंभ होता है। बिहार में लंबे समय तक लालू प्रसाद यादव के प्रभाव के बाद जिस दौर को नीतीश कुमार की राजनीति का युग कहा जाता था, वह अब धीरे-धीरे नए चरण में प्रवेश करता दिखाई दे रहा है। हालांकि यह कहना गलत नहीं होगा कि बिहार की आधुनिक राजनीति में नीतीश कुमार की भूमिका हमेशा याद रखी जाएगी। उनकी प्रशासनिक क्षमता, संतुलित राजनीति और विकास के प्रति प्रतिबद्धता ने बिहार को एक नई पहचान दी। आज जब वे सक्रिय राज्य राजनीति से पीछे हटने की तैयारी में हैं, तो यह बदलाव भी उनकी राजनीतिक परिपक्वता का ही उदाहरण माना जा रहा है। उन्होंने परिस्थितियों को समझते हुए ऐसा रास्ता चुना है जिससे राज्य की राजनीति में नई पीढ़ी और नई ऊर्जा का प्रवेश हो सके।

आने वाले कुछ सप्ताह बिहार की राजनीति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने के बाद नई सरकार के गठन की संभावना है। यदि सब कुछ तय रणनीति के अनुसार होता है तो रामनवमी से पहले बिहार में नई सरकार शपथ ले सकती है। उस स्थिति में राज्य की राजनीति एक नए अध्याय में प्रवेश करेगी। इस प्रकार बिहार की राजनीति में जो बदलाव दिखाई दे रहा है, वह केवल नेतृत्व परिवर्तन नहीं बल्कि भविष्य की नई राजनीतिक दिशा का संकेत भी है। एक ओर अनुभवी नेतृत्व राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय होगा और दूसरी ओर राज्य में नई सरकार विकास की गति को आगे बढ़ाने का प्रयास करेगी। यही कारण है कि इस पूरे घटनाक्रम को बिहार की राजनीति में ऐतिहासिक मोड़ के रूप में देखा जा रहा है।

**कांतिलाल मांडोत**

# संपादकीय

## आधी आबादी का पूरा आकाशः अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का वैश्विक परिप्रेक्ष्य

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, जो हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है, महिलाओं की उपलब्धियों का उत्सव है और लैंगिक समानता की दिशा में संघर्ष का प्रतीक। यह दिन केवल एक तारीख नहीं, बल्कि एक वैश्विक आंदोलन का प्रतीक है जो सदियों से चली आ रही असमानताओं को चुनौती देता है। 1908 में अमेरिका की 15,000 महिलाओं ने न्यूयॉर्क की सड़कों पर उतरकर बेहतर कामकाजी परिस्थितियों, वोट का अधिकार और सम्मानजनक वेतन की मांग की थी। उस आंदोलन ने जन्म लिया, जो आज दुनिया भर में लाखों महिलाओं को प्रेरित करता है। संयुक्त राष्ट्र ने 1975 में इसे आधिकारिक रूप से मान्यता दी, और तब से यह दिन महिलाओं के अधिकारों, उनकी नेतृत्व क्षमता और सामाजिक न्याय की मांग का केंद्र बन गया है। भारत जैसे देश में, जहां महिलाएं प्राचीन काल से देवी के रूप में पूजित होती आई हैं, फिर भी वास्तविकता में उन्हें समान अवसरों से वंचित रखा जाता रहा है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि समानता का स्वप्न अधूरा है, जब तक हर महिला को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सुरक्षा न मिले।

ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारतीय महिलाओं का प्रतिरोध और नेतृत्व कभी थमा नहीं। प्राचीन काल में गार्गी और मैत्रेयी जैसी विदुषियों ने शास्त्रार्थ में अपनी बौद्धिक श्रेष्ठता सिद्ध की, तो मध्यकाल में रानी लक्ष्मीबाई ने अठारह सौ सत्तावन के संग्राम में अपनी वीरता से ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी। आधुनिक भारत की नींव रखने में सावित्रीबाई फुले का योगदान अविस्मरणीय है, जिन्होंने वर्ष 1848 में पुणे में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना की। उस समय जब समाज लड़कियों की शिक्षा को अधर्म मानता था, सावित्रीबाई पर पत्थर और कीचड़ फेंके जाते थे, किंतु उन्होंने हार नहीं मानी। इसी संघर्ष की परिणति थी कि आज भारत की बेटियां अंतरिक्ष से लेकर ओलंपिक के मैदान तक अपना परचम लहरा रही हैं। स्वतंत्रता संग्राम में सरोजिनी नायडू, अरुणा आसफ अली और भीखाजी कामा जैसी महिलाओं ने यह सिद्ध कर दिया कि राष्ट्र की मुक्ति का मार्ग स्त्री की सहभागिता के बिना संभव नहीं है।

आजादी के पश्चात भारतीय संविधान ने अनुच्छेद चौदह और पंद्रह के माध्यम से लैंगिक समानता को मौलिक अधिकार के रूप में प्रतिष्ठित किया। राजनीतिक पटल पर भारत ने विश्व को राह दिखाई जब इंदिरा गांधी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनीं और अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति से वैश्विक भूगोल को बदल दिया। वर्तमान समय में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सर्वोच्च पद पर आसीन होना इस बात का प्रतीक है कि एक साधारण आदिवासी पृष्ठभूमि से आने वाली महिला भी अपनी योग्यता से शिखर तक पहुँच सकती है। राजनीति में महिलाओं की भागीदारी का एक सशक्त उदाहरण पंचायती राज व्यवस्था है, जहाँ तैंतीस से पचास प्रतिशत आरक्षण के कारण आज लगभग चौदह लाख से अधिक महिलाएं सरपंच और पार्षद के रूप में ग्रामीण भारत की तस्वीर बदल रही हैं। हालांकि, संसद और विधानसभाओं में उनकी हिस्सेदारी अभी भी लगभग चौदह प्रतिशत के आसपास सिमटी हुई है, जिसके लिए निरंतर प्रयास और विधायी समर्थन की आवश्यकता है।

आर्थिक मोर्चे पर महिलाओं की स्थिति और उनकी भागीदारी विकास के मापदंडों को निर्धारित करती है। वैश्विक आर्थिक मंच की वर्ष 2023 की रिपोर्ट के अनुसार, भारत लैंगिक अंतराल सूचकांक में 146 देशों के बीच 127वें स्थान पर खड़ा है, जो यह दर्शाता है कि आर्थिक आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में अभी लंबी दूरी तय करनी है। भारत मं महिला श्रम बल भागीदारी दर वर्तमान में लगभग सैंतीस प्रतिशत है, जबकि पुरुषों के मामले में यह आंकड़ा छिहत्तर प्रतिशत से अधिक है। इस अंतर का मुख्य कारण घरेलू उत्तरदायित्वों का असंतुलित बोझ और कार्यस्थलों पर सुरक्षा की कमी है। इसके अतिरिक्त, समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत अभी भी पूर्णतः धरातल पर नहीं उतरा है; आंकड़े बताते हैं कि महिलाओं को पुरुषों की तुलना में लगभग बीस प्रतिशत कम पारिश्रमिक प्राप्त होता है। हालांकि, स्टार्टअप और उद्यमशीलता के क्षेत्र में बदलाव की लहर देखी जा रही है, जहाँ दस में से लगभग दो उद्यम महिलाओं द्वारा संचालित किए जा रहे हैं।

शिक्षा और स्वास्थ्य किसी भी समाज की प्रगति के आधार स्तंभ होते हैं। राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण के पांचवें चरण के आंकड़े बताते हैं कि भारत में महिला साक्षरता दर में सुधार हुआ है और यह सत्तर प्रतिशत के पार पहुँच गई है, किंतु ग्रामीण क्षेत्रों में अब भी पैंसठ प्रतिशत महिलाएं साक्षरता से वंचित हैं। लड़कियों के विद्यालय छोड़ने की दर अभी भी चिंता का विषय है, जिसका मुख्य कारण सुरक्षा, परिवहन की कमी और स्वच्छता संबंधी सुविधाओं का अभाव है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में मातृ मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी आई है, जो प्रति लाख जीवित जन्मों पर संतानबे तक पहुँच गई है, लेकिन कुपोषण और रक्ताल्पता (एनीमिया) अभी भी एक बड़ी चुनौती है। भारत की लगभग संतावन प्रतिशत महिलाएं रक्ताल्पता से पीड़ित हैं, जो उनके कार्यबल और जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। विज्ञान और खेल जगत में भारतीय महिलाओं ने उन रूढ़ियों को तोड़ा है जो उन्हें केवल घर की चारदीवारी तक सीमित मानती थीं। 'मिसाइल वुमन' के नाम से विख्यात टेस्सी थॉमस ने अग्नि मिसाइल परियोजना का नेतृत्व कर यह सिद्ध किया कि तकनीकी कौशल किसी लिंग का मोहताज नहीं है। खेल के मैदान में पीटी उषा की उड़ान से शुरू हुआ सफर आज मैरी कॉम के छह विश्व स्वर्ण पदकों, पीवी सिंधु के ओलंपिक पदकों और मिताली राज के क्रिकेट कीर्तिमानों तक पहुँच चुका है। ये उपलब्धियां केवल पदक नहीं हैं, बल्कि उन करोड़ों लड़कियों के लिए आशा की किरण हैं जो समाज के बंधनों को तोड़कर अपनी पहचान बनाना चाहती हैं।

यद्यपि उपलब्धियां गौरवशाली हैं, परंतु सामाजिक सुरक्षा और अपराध के आंकड़े एक भयावह तस्वीर भी प्रस्तुत करते हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के वर्ष 2022 के आंकड़ों के अनुसार, महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में निरंतर वृद्धि देखी गई है। प्रति घंटे दो से अधिक महिलाओं के साथ होने वाली यौन हिंसा और घरेलू उत्पीड़न के मामले यह बताते हैं कि केवल कानून का निर्माण पर्याप्त नहीं है, बल्कि समाज की चेतना में परिवर्तन अनिवार्य है। उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में बाल विवाह की दर अभी भी चुनौतीपूर्ण स्तर पर है, जो लड़कियों के बचपन और उनके भविष्य को अंधकारमय बना देती है। निर्भया कांड के पश्चात कानून को और अधिक कठोर बनाया गया और त्वरित अदालतों की स्थापना की गई, किंतु न्याय की धीमी प्रक्रिया और सामाजिक लोकलाज अभी भी पीड़ितों के मार्ग की बाधा बनी हुई है।

सरकारी योजनाओं ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में उत्प्रेरक का कार्य किया है। 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' अभियान ने लिंगानुपात में सुधार लाने और कन्या शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसी प्रकार 'उज्ज्वला योजना' के अंतर्गत दस करोड़ से अधिक महिलाओं को निःशुल्क गैस कनेक्शन प्रदान कर उन्हें धुएं से होने वाली बीमारियों से मुक्ति दिलाई गई है। 'मुद्रा योजना' के तहत वितरित ऋणों में लगभग सत्तर प्रतिशत लाभार्थी महिलाएं हैं, जो सूक्ष्म और लघु स्तर पर आर्थिक क्रांति का नेतृत्व कर रही हैं। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से ग्रामीण महिलाएं न केवल आर्थिक रूप से सुदृढ़ हुई हैं, बल्कि वे सामाजिक निर्णय लेने की प्रक्रिया में भी अग्रणी भूमिका निभा रही हैं।

वर्तमान समय में डिजिटल क्रांति ने महिलाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार खोले हैं। 'डिजिटल इंडिया' अभियान के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं ई-कॉमर्स, ऑनलाइन बैंकिंग और शिक्षा से जुड़ रही हैं। कोविड महामारी के दौरान जब दुनिया ठहर गई थी, तब आशा कार्यकर्ताओं के रूप में नौ लाख से अधिक महिलाओं ने अग्रिम पंक्ति में रहकर टीकाकरण और स्वास्थ्य सेवाओं का जिम्मा संभाला। यह उनके अदम्य साहस और समर्पण का ही परिणाम था कि भारत इतनी बड़ी आपदा का सामना कर सका। आज तकनीक के युग में महिलाएं कोडिंग से लेकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक हर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही हैं।

निष्कर्षतः, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि एक प्रतिज्ञा है। यह संकल्प है उस समाज के निर्माण का जहाँ किसी व्यक्ति की क्षमता का आकलन उसके लिंग के आधार पर न होकर उसकी योग्यता के आधार पर हो। महिला सशक्तिकरण का अर्थ केवल महिलाओं को अधिकार देना नहीं है, बल्कि उन्हें एक ऐसा वातावरण प्रदान करना है जहाँ वे अपनी इच्छाओं और सपनों को बिना किसी भय के जी सकें। जैसा कि मलाला यूसुफजई ने कहा था कि हम तब तक सफल नहीं हो सकते जब तक हमारी आधी आबादी को पीछे रखा जाएगा। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का स्वप्न तभी साकार होगा जब देश की प्रत्येक महिला शिक्षित, सुरक्षित और आर्थिक रूप से स्वतंत्र होगी। यह संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक समानता का अधिकार केवल कागजों तक सीमित न रहकर हर घर और हर दिल की हकीकत न बन जाए। आज हमें यह प्रण लेना होगा कि हम अपनी बेटियों को केवल पढ़ाएंगे ही नहीं, बल्कि उन्हें गगन चूमने के लिए पंख भी देंगे।

**महेन्द्र तिवारी**

# कनाडा यूरेनियम डीलः भारत की ऊर्जा क्रांति या पर्यावरणीय संकट की शुरुआत?

**[ कनाडा से यूरेनियमः नेट-जीरो का रास्ता या रेडिएशन का साया? ]**

**[ न्यूक्लियर पावर का नया अध्यायः क्या भारत पर्यावरण न्याय को भूल जाएगा? ]**

ऊर्जा के मोर्चे पर भारत एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है, जहाँ भविष्य की दिशा तय हो रही है–एक ऐसा भविष्य जहाँ बिजली की कमी अतीत बन जाए, कारखानों की चिमनियों से उठता धुआँ कम हो और हर घर तक पहुँचने वाली ऊर्जा कोयले की कालिख नहीं बल्कि स्वच्छ स्रोतों से पैदा हो। यह सपना केवल विकास का नहीं, बल्कि जलवायु सुरक्षा का भी है। लेकिन इस उजले भविष्य की राह में कुछ अंधेरे भी छिपे हैं। मार्च 2026 में भारत और कनाडा के बीच हुई अरबों डॉलर की यूरेनियम डील ने इसी द्वंद्व को फिर सामने ला खड़ा किया है। एक ओर यह समझौता ऊर्जा सुरक्षा और कम कार्बन उत्सर्जन का वादा करता है, तो दूसरी ओर खनन, रेडिएशन और पर्यावरणीय खतरों की चिंता भी बढ़ाता है। सवाल है कि क्या यह डील भारत के क्लाइमेट भविष्य को सुरक्षित बनाएगी या यह विकास की ऐसी कीमत होगी जिसे पर्यावरण और आदिवासी समुदायों को चुकाना पड़ेगा?

ऊर्जा सुरक्षा और रणनीतिक सहयोग की दिशा में भारत-कनाडा समझौता एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। यह केवल व्यापारिक सौदा नहीं बल्कि रणनीतिक साझेदारी का प्रतीक भी है। इस डील के तहत कनाडा की खनन कंपनी कैमेको भारत को 2027 से 2035 के बीच लगभग 22 मिलियन पाउंड यूरेनियम देगी, जिससे भारत के 24 परमाणु रिएक्टरों को ईंधन मिलेगा। भारत की वर्तमान परमाणु ऊर्जा क्षमता लगभग 8.88 गीगावाट है, जिसे सरकार 2047 तक लगभग 100 गीगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखती है। इसके लिए छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर और उन्नत परमाणु तकनीकों पर सहयोग की भी चर्चा है। बढ़ती ऊर्जा मांग और रूस जैसे पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर वैश्विक दबाव के बीच यह समझौता भारत को एक वैकल्पिक और अपेक्षाकृत स्वच्छ ऊर्जा मार्ग दे सकता है, इसलिए इसे ऊर्जा रणनीति का महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

जलवायु परिवर्तन की चुनौती के बीच परमाणु ऊर्जा को अक्सर एक संभावित समाधान के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। भारत ने 2070 तक नेट-जीरो उत्सर्जन और 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य रखा है। इस परिप्रेक्ष्य में परमाणु ऊर्जा एक स्थिर बेसलोड प्रदान कर सकती है, जो सौर और पवन ऊर्जा की अनियमितता को संतुलित करती है। अध्ययनों के अनुसार परमाणु ऊर्जा से बिजली उत्पादन में कार्बन उत्सर्जन कोयले से कई गुना कम होता है, इसलिए यह जलवायु परिवर्तन से निपटने का महत्वपूर्ण साधन बन सकती है। लेकिन ऊर्जा के इस स्वच्छ चेहरे के पीछे एक जटिल वास्तविकता भी छिपी है–यूरेनियम के खनन, प्रसंस्करण और अपशिष्ट प्रबंधन की प्रक्रिया पर्यावरणीय जोखिमों से भरी हुई है।

ऊर्जा की चमकदार बहस में यूरेनियम खनन के पर्यावरणीय दुष्प्रभाव अक्सर दबकर रह जाते हैं। खदानों से निकलने वाले रेडियोधर्मी टेलिंग्स यानी अपशिष्ट में थोरियम और रेडियम जैसे तत्व मौजूद रहते हैं, जो लंबे समय तक मिट्टी और जल स्रोतों को दूषित कर सकते हैं। कनाडा के सस्कैचेवान क्षेत्र में स्थित कई यूरेनियम खदानों के आसपास भूजल प्रदूषण और वन्यजीवों पर प्रभाव को लेकर समय-समय पर चिंताएँ उठती रही हैं। हालांकि, नियामक रिपोर्ट्स में कुछ साइटों पर सफाई प्रयास चल रहे हैं। भारी मात्रा में पानी के उपयोग और खनन के दौरान उत्पन्न कार्बन उत्सर्जन भी इस प्रक्रिया को पूरी तरह 'स्वच्छ' नहीं रहने देते। यही कारण है कि कई पर्यावरण विशेषज्ञों का मानना है कि परमाणु ऊर्जा के पूरे जीवन चक्र को ध्यान में रखे बिना इसे जलवायु समाधान के रूप में प्रस्तुत करना अधूरा दृष्टिकोण है। इस पूरी बहस का सबसे संवेदनशील पहलू आदिवासी समुदायों से जुड़ा हुआ है। कनाडा में जिन क्षेत्रों में यूरेनियम खनन होता है, वहाँ डेने, क्री और मेटिस जैसे इंडिजिनस समुदाय सदियों से रहते आए हैं। कई सामाजिक संगठनों का दावा है कि इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को रेडिएशन से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ा है। फेफड़ों के कैंसर, जेनेटिक विकार और अन्य बीमारियों के मामलों को लेकर वर्षों से चिंता व्यक्त की जाती रही है। कई आदिवासी समूहों का आरोप है कि उनकी जमीनों का इस्तेमाल खनन के लिए किया जाता है, लेकिन निर्णय प्रक्रिया में उनकी सहमति और अधिकारों को पर्याप्त महत्व नहीं दिया जाता।

परमाणु ऊर्जा की यह बहस केवल वैश्विक नहीं, भारत में भी उतनी ही तीव्रता से गूंजती है। झारखंड की जादुगुडा यूरेनियम खदान इसका सबसे चर्चित उदाहरण है, जहाँ स्थानीय हो, संताल और मुंडा आदिवासी दशकों से स्वास्थ्य और पर्यावरण संबंधी चिंताओं को उठाते रहे हैं। कई अध्ययनों में इस क्षेत्र में जन्मजात विकृतियों, कैंसर और अन्य बीमारियों के मामलों को लेकर सवाल उठे हैं। स्वतंत्र अध्ययन इसकी पुष्टि करते हैं, हालांकि यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इसे अस्वीकार करता है। टेलिंग पॉन्ड्स से रिसाव की घटनाएँ और जल स्रोतों में भारी धातुओं की मौजूदगी ने स्थानीय लोगों के जीवन को प्रभावित किया है। इन परिस्थितियों में जब परमाणु ऊर्जा विस्तार की बात होती है, तो यह सवाल भी उठता है कि क्या विकास की कीमत हमेशा उन्हीं समुदायों को चुकानी पड़ेगी जो पहले से ही हाशिये पर हैं। इन चुनौतियों के बावजूद समाधान की संभावनाएँ भी मौजूद हैं। यदि परमाणु ऊर्जा को वास्तव में जलवायु समाधान बनाना है तो खनन से लेकर अपशिष्ट प्रबंधन तक हर चरण में कड़े पर्यावरणीय मानकों को लागू करना होगा। मजबूत पर्यावरणीय प्रभाव आकलन, पारदर्शिता और स्थानीय समुदायों की भागीदारी अत्यंत आवश्यक है। आदिवासी समुदायों के लिए 'फ्री, प्रायर एंड इन्फॉर्म्ड कंसेंट' यानी पूर्व सहमति की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए। साथ ही नई तकनीकों जैसे छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर और उन्नत अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों पर भी गंभीर निवेश जरूरी है। इससे परमाणु ऊर्जा के जोखिमों को कम करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा सकते हैं।

ऊर्जा, पर्यावरण और न्याय के चौराहे पर खड़ी भारत-कनाडा यूरेनियम डील एक महत्वपूर्ण परीक्षा बन गई है। अंततः यह केवल ऊर्जा का सवाल नहीं है, बल्कि विकास, पर्यावरण और न्याय के बीच संतुलन की भी कसौटी है। यदि यह समझौता जिम्मेदार नीतियों और मजबूत निगरानी के साथ लागू किया जाता है, तो यह भारत के क्लाइमेट लक्ष्यों को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। लेकिन अगर पर्यावरणीय जोखिमों और आदिवासी अधिकारों की अनदेखी की गई, तो यह डील एक नई समस्या का कारण भी बन सकती है। इसलिए असली सवाल यही है–क्या हम ऐसा विकास मॉडल चुनेंगे जो ऊर्जा सुरक्षा के साथ-साथ प्रकृति और मानव गरिमा की भी रक्षा करे? भारत के क्लाइमेट भविष्य का उत्तर शायद इसी संतुलन में छिपा है।

**प्रो. आरके जैन 'अरिजीत'**

# राज्यसभा के रास्ते नीतीश कुमार का वानप्रस्थ गमन!

नीतीश कुमार ने अब राज्यसभा का पर्चा भर कर वानप्रस्थ गमन का रास्ता चुन लिया है। पिछले करीब 20 सालों से बिहार की राजनीति के केंद्र में नीतीश कुमार का दबदबा रहा है । सरकारें बदलीं, गठबंधन बदले, चुनाव आए-गए, लेकिन एक छोटी सी अवधि को छोड़ दिया जाए तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नीतीश कुमार ही बने रहे। 2005 से बिहार की राजनीति को दिशा देने वाले इस नेता ने अब राज्यसभा जाने की तैयारी कर ली है, और इसके साथ ही सूबे की सियासत में एक बड़ा बदलाव शुरू होने वाला लगता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा राज्यसभा का नामांकन भरने से यह बात स्पष्ट हो गयी है कि बिहार की राजनीति से एक युग का अब अवसान होने जा रहा है। बिहार की राजनीति में पिछले दो दशकों से यदि किसी एक नेता का सबसे अधिक प्रभाव रहा है, तो वह नाम है नीतीश कुमार। वर्ष 2005 से लेकर अब तक बिहार की सत्ता का केंद्र लगभग लगातार उनके इर्द-गिर्द ही घूमता रहा है। अलग-अलग गठबंधनों, बदलते राजनीतिक समीकरणों और कई चुनावी उतार-चढ़ावों के बावजूद उन्होंने मुख्यमंत्री पद पर अपनी पकड़ बनाए रखी। ऐसे में नीतीश के द्वारा मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने का ऐलान बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव के रुप में देखा जा रहा है। अगर देखा जाए लगभग साढ़े तीन दशकों तक बिहार की राजनीति दो नामों के इर्द-गिर्द भूमती रही, ये दो नाम हैं लालू प्रसाद यादव और नीतीश। इन दोनों नेताओं ने न केवल बिहार की सत्ता को आकार दिया, बल्कि राज्य की सामाजिक, राजनीतिक और प्रशासनिक दिशा भी तय की। अब जब दोनों ही नेता सक्रिय राजनीति से दूर हो रहे हैं, तब बिहार एक नए दौर के मुहाने पर खड़ा दिखाई दे रहा है। 1990 के दशक में जब लालू प्रसाद यादव सत्ता में आए, तब बिहार की राजनीति में एक नई सामाजिक चेतना का उदय हुआ। लालू ने 'सामाजिक न्याय' को केवल एक राजनीतिक नारा नहीं रहने दिया, बल्कि इसे एक आंदोलन का रूप दिया। पिछड़े वर्गों, दलितों और वंचित समुदायों की राजनीतिक भागीदारी को उन्होंने केंद्र में रखा। लंबे समय से सत्ता के गलियारों से दूर रहे वर्गों को उन्होंने राजनीतिक पहचान और आवाज दी। सत्ता की भाषा बदली, राजनीतिक चेहरे बदले और शासन के केंद्र में सामाजिक प्रतिनिधित्व की नई धारा दिखाई देने लगी। इसमें कोई दोमत नहीं है कि जेपी आंदोलन से निकले नेताओं की एक पूरी पीढ़ी ने पिछले तीन दशकों तक बिहार की राजनीति को दिशा दी। इस पीढ़ी में पुरानी पीड़ी के पीछे हटने का अर्थ है कि बिहार की राजनीति में नई पीढ़ी के नेताओं को अवसर मिलेगा। इन सबके बीच अगर बात नीतीश की की जाए तो, बिहार की राजनीति में उनकी भूमिका केवल एक मुख्यमंत्री की नहीं रही है, बल्कि वे लंबे समय तक राज्य की राजनीति के सर्वमान्य नेता रहे हैं। विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं के लोग भी उन्हें स्वीकार करते रहे हैं। गठबंधन की राजनीति में कई बार वैचारिक मतभेद होने के बावजूद उन्होंने गठबंधन धर्म निभाया और राजनीतिक संतुलन बनाए रखा। उनकी खास पहचान उनकी सामाजिक योजनाओं और प्रशासनिक छवि से बनी। खास तौर पर महिलाओं के बीच उनकी पकड़ काफी मजबूत रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में भी महिलाओं का समर्थन एनडीए की जीत का एक बड़ा कारण माना गया था। इसी कारण जब तक वह बिहार की राजनीति में सक्रिय थे, तब तक विपक्षी दलों के लिए उन्हें सीधे चुनौती देना आसान नहीं था। हालांकि, इसी दौर में बिहार की छवि पर कई सवाल भी उठे। कानून-व्यवस्था की स्थिति को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना हुई और 'जंगलराज' जैसे शब्द राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बन गए। विकास की रफ्तार धीमी पड़ने और उद्योगों के बंद होने से बिहार की अर्थव्यवस्था कमजोर होती गई। राज्य से बड़े पैमाने पर पलायन शुरू हुआ और बिहार प्रवासी मजदूरों के प्रदेश के रूप में पहचाना जाने लगा। चीनी मिलों, जूट फैक्ट्रियों और कई छोटे उद्योगों के बंद होने से रोजगार के अवसर घटते गए। इस दौर में बिहार की पहचान सामाजिक न्याय की राजनीति के साथ-साथ पिछड़ेपन और आर्थिक संकट से भी जुड़ने लगी। साल 2005 में बिहार की राजनीति ने एक बड़ा मोड़ लिया जब नीतीश कुमार सत्ता में आए।

यह केवल सत्ता परिवर्तन नहीं था, बल्कि राजनीतिक प्राथमिकताओं में बदलाव की शुरुआत भी थी। नीतीश कुमार ने सामाजिक न्याय की राजनीति को विकास और प्रशासनिक सुधारों के साथ जोड़ने की कोशिश की। उन्होंने बुनियादी ढांचे के विकास को प्राथमिकता दी और बिहार में सड़कों तथा पुलों का व्यापक जाल बिछाया। राज्य के दूरदराज इलाकों को राजधानी पटना से बेहतर तरीके से जोड़ने का प्रयास किया गया। एक समय ऐसा था जब बिहार के कई जिलों से पटना पहुंचने में पूरा दिन लग जाता था, लेकिन सड़क नेटवर्क के विस्तार के बाद यात्रा का समय काफी कम हो गया। यह बदलाव केवल भौतिक संरचना का नहीं था, बल्कि राज्य की मानसिकत्ता और विकास की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम था। नीतीश कुमार ने शासन को अधिक प्रशासनिक रूप देने की कोशिश की और कानून-व्यवस्था को राजनीतिक विमर्श के केंद्र में लाया। उनकी सरकार द्वारा शुरू की गई कई योजनाओं ने समाज पर गहरा प्रभाव डाला। छात्राओं के लिए साइकिल योजना ने शिक्षा के क्षेत्र में एक नया बदलाव लाया। पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण देने से स्थानीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी। छात्रवृत्ति और प्रोत्साहन योजनाओं ने ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा दिया। इन कदमों ने बिहार की सामाजिक संरचना को धीरे-धीरे बदलने में भूमिका निभाई। नीतीश कुमार की छवि 'सुशासन बाबू' के रूप में स्थापित हुई। उन्होंने प्रशासनिक सुधार, कानून-व्यवस्था और बुनियादी विकास को अपनी राजनीति का आधार बनाया। उनके शासनकाल में बिहार की छवि धीरे-धीरे बदलने लगी। रष्ट्रीय स्तर पर भी बिहार को विकास के नए प्रयासों के संदर्भ में चर्चा मिलने लगी। विहार के विकास में उनके योगदान को हमेशा याद रखा जायेगा। बिहार में सड़कों, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और कानून-व्यवस्था के क्षेत्र में जो बदलाव हुए, उससे राज्य में परिवर्तन आया। मगर भूलना नहीं चाहिए कि राजनीति में बदलाव हमेशा अनिश्चितता लेकर आता है। नीतीश के संभावित फैसले से भी बिहार की राजनीति में कई नए सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या जदयू अपनी पुरानी ताकत बनाए रख पाएगी? क्या भाजपा बिहार में अपना मुख्यमंत्री चनाएगी ? क्या नई पीढ़ी के नेताओं को मौका मिलेगा ? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार राष्ट्रीय राजनीति में नई भूमिका निभाएंगे ? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले समय में ही मिलेंगे। लेकिन इतना तय है कि कुमार का यह फैसला केवल एक व्यक्ति के पद परिवर्तन की कहानी नहीं है। यह बिहार की राजनीति के एक लंबे अध्याय के समापन और एक नए अध्याय की शुरुआत का संकेत है।

आपको बता दें नीतीश का राज्यसभा जाना सिर्फ पद का बदलाव नहीं है; यह करीब 5 दशक लंबी राजनीतिक यात्रा का एक नया अध्याय भी हो सकता है। हाल ही में नीतीश कुमार ने खुद कहा है कि अपनी लंबी राजनीतिक जिंदगी में वे बिहार विधानसभा के सदस्य, विधान परिषद के सदस्य और लोकसभा के सांसद रह चुके हैं। अब वे राज्यसभा में भी सेवा देना चाहते हैं। और उसके बाद अगर उन्हें केंद्र सरकार में कोई भूमिका मिली, तो बिहार की राजनीति का यह बड़ा चेहरा फिर से राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते दिख सकता है। राजनीति में समय के साथ भूमिकाएं बदलती रहती हैं, लेकिन कुछ नेता ऐसे होते हैं जिनकी छाया लंबे समय तक बनी रहती है। नीतीश भी ऐसे ही नेताआ में गिने जाते हैं। मुख्यमंत्री के रूप में उनकी भूमिका चाहे समाप्त हो जाए, लेकिन बिहार और राष्ट्रीय राजनीति में उनकी मौजूदगी आगे भी चर्चा और प्रभाव का विषय बनी रहेगी।

आपको बता दें 2020 के बाद एनडीए में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन गई थी। सीटों की संख्या साफ दिखा रही थी कि भाजपा के पास ज्यादा विधायक हैं, फिर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहे। आखिर ऐसा क्यों? इसके 2 मुख्य कारण अक्सर बताए जाते हैं। पहला कारण उनकी सामाजिक आधार है। बिहार में नीतीश कुमार ने अति पिछड़े वर्गों और महिला मतदाताओं से बहुत मजबूत जुड़ाव बनाया है। शराबबंदी जैसी नीतियां और महिलाओं के लिए कल्याण योजनाओं ने उन्हें एक भरोसेमंद और विश्वसनीय नेता की छवि दी है।75 साल की उम्र में स्वास्थ्य कारणों से नीतीश कुमार अब कम मेहनत वाला रोल चुनना चाहते हैं। ऐसे में राज्यसभा उनके लिए एक सम्मानजनक और महत्वपूर्ण मंच हो सकता है। लेकिन बात यहां सिर्फ पद बदलने की नहीं है। यह पार्टी के भविष्य को सुरक्षित करने की कोशिश भी हो सकती है। चर्चा है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार जल्द ही सक्रिय राजनीति में आ सकते हैं और उन्हें राज्य सरकार में कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा सकती है।

**मनोज कुमार अग्रवाल**

मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक रवि कुमार अवस्थी द्वारा सुशीला स्टेडी बेल एकेडमी 117-मोहल्ला विजय लक्ष्मी नगर परगना खैराबाद तहसील व जनपद -सीतापुर से प्रकाशित तथा महावीर आफसेट 28, हीवेट रोड लखनऊ से मुद्रित। सम्पादक रवि कुमार अवस्थी समाचार पत्र में छपे समस्त समाचार संवाददाताओं के अपने श्रोत एवं संकलन हैं, जिनसे सम्पादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। **नोटः**-उपरोक्त सभी पद अवैतनिक एवं स्वयंसेवी हैं तथा समाचार पत्र से सम्बंधित सारे विवादो का न्याय क्षेत्र सीतापुर होगा। R.N.I NO. UPHIN/2012/43078 मो0 नं0 -9511151254, E-Mail :- news@swatantraprabhat .com

## संक्षिप्त खबरें

### रोजगार सेवको ने BDO को दिया ज्ञापन

**काँट, शाहजहांपुर।** विकासखंड काँट के ग्राम रोजगार सेवकों सहित समस्त मनरेगा कर्मचारीयों का 7 से 13 महीने का मानदेय बकाया है यहां तक की पिछली दीपावली के त्यौहार पर और इस बार होली के त्यौहार पर भी ग्राम रोजगार सेवकों सहित किसी भी मनरेगा कर्मचारी को मानदेय नहीं दिया गया इससे परिवार के सामने आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है आज दिनांक 7 मार्च 2026 को मनरेगा कर्मचारी महासंघ उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में विकासखंड पर समस्त मनरेगा कर्मचारीयों ने बैठक कर मानदेय सहित तमाम समस्याओं से संबंधित ज्ञापन खंड विकास अधिकारी को सौपा। बैठक में मुख्य रूप से ब्लॉक अध्यक्ष अर्वेश कुमार वर्मा ब्लॉक वरिष्ठ उपाध्यक्ष जगदीश सिंह, वीरपाल सिंह, सर्वेश कुमार यादव मोबीन, वीरपाल सिंह, अजय कुमार, रविकांत त्रिपाठी, अंकिता अग्निहोत्री आदर्श जायसवाल आदि तमाम साथी उपस्थित रहे।

### पंचायत चुनाव : वीडियोग्राफी की व्यवस्था कराने हेतु जेम पोर्टल पर कस्टम बिड प्रकाशित

**इच्छुक फर्मे निविदा में ले सकते है भाग : अंजू लता**

**रायबरेली:-** मुख्य विकास अधिकारी/प्रभारी अधिकारी जिला निर्वाचन कार्यालय (पंचायत एवं नगरीय निकाय) रायबरेली अंजूलता ने बताया है कि राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश लखनऊ के निर्देशानुसार त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन, 2026 हेतु आयोग के मानक के अन्तर्गत सामान्य निर्वाचन की विभिन्न प्रक्रिया के दौरान प्रमुख घटनाओं की वीडियोग्राफी की व्यवस्था कराने हेतु जेम पोर्टल पर जेम बिड संख्या GEM/2026/B/7329425 दिनांक 07 मार्च 2026 को प्रकाशित कर दी गयी है, बिड बंद होने की तिथि 17 मार्च 2026 समय अपरान्ह 14:00 बजे तथा बिड खुलने की तिथि 17 मार्च 2026 को समय अपरान्ह 14:30 बजे है तथा उपरोक्त व्यवस्थाओं की कुल अनुमानित लागत रू0 20,00,000/- (मु0 बीस लाख मात्र) है। इच्छुक फर्मे/संस्था जेम पोर्टल पर आमंत्रित उपरोक्त जेम निविदा में भाग ले सकते हैं। इस निविदा में जेम के नियम एवं शर्तों के साथ-साथ इस कार्यालय द्वारा निर्धारित बिड की शर्ते (ATC) लागू होगी। सक्षम प्राधिकारी को बिना कारण बताये निविदा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

### सड़क हादसे में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत

**अज्ञात बाइक सवार पर मुकदमा दर्ज**

**ललितपुर।** तालबेहट के ग्राम रारा के पास हुए एक सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए युवक की ग्वालियर में इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के भाई की तहरीर पर अज्ञात मोटरसाइकिल चालक के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ग्राम रारा निवासी रामचरन कुशवाहा ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनका छोटा भाई कामता पुत्र परसादी बीते मंगलवार, × मार्च की रात करीब 8 बजे घर लौट रहा था। इसी दौरान गांव के पास ही पीछे से आ रही तेज र तार मोटरसाइकिल (यूपी 94 वाई 1857) ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कामता लहूलुहान होकर वहीं सड़क पर गिर पड़ा। परिजनों ने आनन-फानन में घायल कामता को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तालबेहट में भर्ती कराया, जहां सिर की गंभीर चोट को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। हालत में सुधार न होने पर उसे वहां से भी ग्वालियर रेफर किया गया। बीते तीन दिनों से जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे कामता ने शुक्रवार, 6 मार्च को इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। घटना के संबंध में थाना तालबेहट पुलिस ने मृतक के भाई की शिकायत पर अज्ञात बाइक चालक के खिलाफ बीएनएस की धारा 281, 125(बी) और 106(1) के तहत मुकदमा पंजीकृत किया है।

## बीडीएस की पढ़ाई पूरी कर डेंटल सर्जन बने शिवांक द्विवेदी

**स्वतंत्र प्रभात संवाददाता**

**लालगंज (रायबरेली)।** क्षेत्र के छमनीखेड़ा मजरे रायपुर मझिगवां गांव निवासी सेवानिवृत्त फौजी राजेश द्विवेदी के बेटे शिवांक द्विवेदी ने बीडीएस की पढ़ाई पूरी कर ली है। अब वह डेंटल सर्जन के रूप में अपने करियर की शुरुआत करेंगे। इस उपलब्धि से परिवार और क्षेत्र में खुशी का माहौल है। परिजनों और शुभचिंतकों ने उन्हें बधाई दी है। नीट परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद शिवांक का चयन सिकंदराबाद स्थित आर्मी कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस एंड रिसर्च में हुआ था। यहां उन्होंने दंत चिकित्सा की पढ़ाई पूरी की। शनिवार को आयोजित दीक्षांत समारोह में उन्हें औपचारिक रूप से बीडीएस की डिग्री प्रदान की गई। शिवांक की शुरुआती पढ़ाई भोजपुर स्थित विवेकानंद चिल्ड्रन एकेडमी में हुई। इसके बाद उन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण की। पहले ही प्रयास में नीट परीक्षा पास कर उन्होंने बीडीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त किया। उनके पिता राजेश द्विवेदी आर्मी मेडिकल कोर से सेवानिवृत्त हैं। मां सोना द्विवेदी गृहिणी हैं। छोटी बहन प्रियम द्विवेदी एमबीए की पढ़ाई कर रही हैं। शिवांक की सफलता से परिवारीजनों में उत्साह है। बाबा सेवानिवृत्त शिक्षक शिवभूषण द्विवेदी, संतोष द्विवेदी,पवन द्विवेदी, कमलाकांत मिश्रा, सुमन शुक्ला, संतोष सिंह, एसके द्विवेदी, सत्यम त्रिपाठी, शिवम शुक्ला, निशांत पांडेय सहित तमाम लोगों ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है।

## घर के अंदर फंदे से लटकी मिली विवाहिता, हत्या का आरोप

● **परिवारीजनों ने अस्पताल में जमकर काटा हंगामा**

**अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित किया**

**स्वतंत्र प्रभात संवाददाता**

**लालगंज (रायबरेली)।** कोतवाली क्षेत्र के सैमसी गांव में शुक्रवार देर शाम एक विवाहिता ने संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगा ली। परिजन उसे गंभीर हालत में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे। जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। घटना से परिवार में कोहराम मच गया। मृतका के घर वालों ने बताया कि गांव निवासी रिचा शर्मा (24) पत्नी अंकित शर्मा ने घर के कमरे में छत के पंखे के हुक से साड़ी के सहारे फांसी लगा ली। उस समय उसका पति अंकित खेत में पानी लगाने गया था। ससुर अवधेश शर्मा मवेशियों की देखरेख कर रहे थे। शाम को जब अंकित खेत से घर लौटा तो रिचा फंदे से झूलती मिली। आनन फानन में फंदा काटकर उसे उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। वहां डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की खबर मिलते ही परिवार में मातम छा गया। परिवारिजनों ने बताया कि रिचा का विवाह वर्ष 2020 में अंकित शर्मा के साथ हुआ था। वह अपने पीछे पांच वर्षीय बेटे शिवांश को छोड़ गई है। सूचना पर अस्पताल पहुंचे मायके पक्ष के लोगों ने हंगामा किया और ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया। पुलिस ने समझा बुझाकर स्थिति को शांत कराया। प्रभारी निरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है।

### बाइक की टक्कर से सड़क पार कर रहा बालक घायल

**लालगंज (रायबरेली)।** कोतवाली क्षेत्र के बाल्हेमऊ नहर पुलिया के निकट शनिवार को सड़क हादसे में एक नौ वर्षीय बालक गंभीर रूप से घायल हो गया। सड़क पार करते समय तेज रफ्तार बाइक ने उसे टक्कर मार दी। गांव की रहने वाली गुड़िया वहां सड़क किनारे दुकान लगाती हैं। शनिवार दोपहर उनका बेटा ऋतिक सड़क पार कर दूसरी ओर जा रहा था। इसी दौरान रायबरेली की ओर से आ रही एक तेज रफ्तार बाइक ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही बालक सड़क पर गिर पड़ा और गंभीर रूप से घायल हो गया। आसपास मौजूद लोगों ने उसे उठाकर उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। अस्पताल में डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार किया। बालक की हालत गंभीर देखते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।

### सड़क पर मृत पड़े मवेशी से टकराकर बाइक सवार युवक घायल

**ग्राम प्रधान प्रतिनिधि राजेश फौजी ने दिखाई मानवीय संवेदना**

**लालगंज (रायबरेली)।** कोतवाली क्षेत्र के बाल्हेमऊ गांव के निकट देर रात सड़क पर पड़ा मृत मवेशी एक हादसे का कारण बन गया। राजेश पासवान पुत्र रामप्रताप निवासी पूरे कालिका बक्स मजरे ऐहार शनिवार रात लगभग 11:30 बजे बाल्हेमऊ गांव के पास से बाइक से गुजर रहे थे। अंधेरे में सड़क पर पड़े मृत मवेशी से उनकी बाइक टकरा गई, जिससे वह घायल हो गए और बाइक भी क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे की जानकारी मिलते ही ऐहार गांव के प्रधान प्रतिनिधि राजेश फौजी मौके पर पहुंचे। मानवीय संवेदना दिखाते हुए प्रधान प्रतिनिधि ने अन्य ग्रामीणों की मदद से फौरन अपने वहां से उन्होंने घायल राजेश को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। जहां उनका इलाज किया गया। इस दौरान डॉ. दिनेश यादव, इंद्रेश यादव और भोला मिश्रा सहित अन्य लोगों ने सहयोग करते हुए घायल और मृत मवेशी को सड़क से हटाया, जिससे आवागमन सामान्य हो सका। ग्रामीणों ने बताया कि सड़क पर पड़े मृत जानवरों को समय पर हटाने की व्यवस्था न होने से इस तरह के हादसे अक्सर होते हैं। लोगों ने प्रशासन से अपील की है कि इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं, ताकि यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

## सम्पूर्ण समाधान दिवस में 76 शिकायतें प्राप्त, 12 का मौके पर निस्तारण

**स्वतंत्र प्रभात संवाददाता**

**बिसवां सीतापुर** राजागणपति आर जिलाधिकारी डा0 राजागणपति आर0 ने तहसील बिसवां में आयोजित सम्पूर्ण समाधान दिवस में भाग लेने से पूर्व आयुष्मान आरोग्य मंदिर जहांगीराबाद का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी प्रसव कक्ष पहुंचे, जहां अव्यवस्थाएं पाए जाने पर उन्होंने कड़ी नाराजगी व्यक्त की। स्टाफ नर्स अनुपस्थित मिलने पर एक दिन का वेतन काटने, चिकित्सक के अनुपस्थित पाए जाने पर उनका भी एक दिन का वेतन काटने तथा दवाओं के रख-रखाव में लापरवाही मिलने पर फार्मासिस्ट को प्रतिकूल प्रविष्टि जारी करते हुए एक दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए। इसके साथ ही कमियां मिलने पर प्रभारी चिकित्साधिकारी बिसवां से स्पष्टीकरण तलब करने के निर्देश भी दिए गए। जिलाधिकारी ने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप सभी मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं। निरीक्षण के दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी सुरेश कुमार सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।इसके बाद तहसील सभागार में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में सम्पूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया।

इस दौरान विभिन्न विभागों से संबंधित कुल 76 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिनमें से 12 मामलों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया तथा शेष शिकायतों को संबंधित विभागों को समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए गए। प्राप्त शिकायतों में राजस्व विभाग की 17, पुलिस विभाग की 38, विकास विभाग की 9, नगर पालिका की 2, विद्युत विभाग की 4 तथा अन्य विभागों की 6 शिकायतें शामिल रहीं। अधिकारियों ने फरियादियों की समस्याएं सुनकर संबंधित विभागों को शीघ्र समाधान के निर्देश दिए।इस अवसर पर उप जिलाधिकारी शिखा शुक्ला तहसीलदार उमाशंकर त्रिपाठी पुलिस क्षेत्राधिकारी अमन सिंह सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

## दरगाह हज़रत बड़े मखदूम साहब में हुआ कार्यक्रम

● **रोज़ा भूखा रहने का नाम नहीं है इसके लिए हमें अल्लाह और उसके रसूल के बनाए नियमों की पाबन्दी करना अनिवार्य,और रोज़ा पूरे शरीर का होता है:- हसन साकिब तय्यब**

**स्वतंत्र प्रभात संवाददाता**

**खैराबाद सीतापुर** रमजानुल मुबारक महीने का समापन होने वाला है और मस्जिदों में हाफ़िज़े क़ुरआन नमाज़ तरावीह के ज़रिए क़ुरआन सुना रहे हैं जो अब धीरे धीरे समापन की ओर बढ़ रहा है। इसी क्रम में विगत रात्रि स्थानीय दरगाह हज़रत बड़े मखदूम साहब में स्थित मस्जिद में क़ुरआन पाक तरावीह के दौरान मुकम्मल हुई यहां पर दरगाह के सज्जादा नशीन शोएब मियां के सुपुत्र हाफ़िज़ अरसलान हसनी ने मुकम्मल करवाया,ज्ञात रहे कि हाफ़िज़ अरसलान हसनी विगत 2024 से लगातार तरावीह पढ़ा रहे हैं। इनके पढ़ाने से लोगों में बड़ी खुशी दिखाई दे रही थी इस समापन अवसर पर नमाज़ पढ़ने वालों ने हाफ़िज़ अरसलान को नज़राना और ढेरों उपहार देते हुए आशीर्वाद भी दिया इस अवसर पर हाफ़िज़ अरसलान के पिता शोएब मियां और आपके बड़े सुपुत्र हसन साकिब तय्यब जो धर्म गुरु की शिक्षा ग्रहण कर रहे है इन दोनों ही लोगों की खुशी देखने के काबिल थी जब आवाम आपके बेटे की कामयाबी की मुबारकबाद उन्हें दे रहे थे इस पर शोएब मियां ने कहा कि यह सब अल्लाह का शुक्र व एहसान है और मेरे वालिद और मेरे बुजुर्गों की दुआओं का नतीजा है जो आज यह दिन देखने को मिला।

इस अवसर पर जन समुदाय को संबोधित करते हुए हसन साकिब उस्मानी तय्यब मियां ने कहा कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया था कि जिसने क़ुरआन को मजबूती से पकड़ लिया वो कभी परेशान और गुमराह न होगा लेकिन अफ़सोस कि क़ुरआन को प्रतिदिन पढ़ना तो दूर की बात है रमज़ान शरीफ़ में भी इसका अध्ययन नहीं करते हैं नमाज़ की पाबन्दी तो हमारे पास है ही नहीं और खासकर तरावीह को खिलवाड़ बना लिया है जिसको देख कर अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब हमारे पास नमाज़ की कोई अहमियत ही नहीं रह गई है उसको तमाशा बना लिया है।

श्री हसन ने आगे कहा कि इस माह में सुबह से कुछ न खाना न पीना इसको रोज़ा नहीं कहते है बल्कि रोज़ा नाम है परहेजगारी का नियमानुसार कार्य करने का, हमें रोज़े की हालत में अपने हाथ पैर आंख मुंह सभी को सही रखना है ग़रीबों की मदद करना ज़रूरत मंद की ज़रूरत को पूरा करना चाहिए जिससे अल्लाह और उसका हबीब भी ख़ुश होता है। इसके बाद सज्जादा नशीन नजमुल हसन शोएब मियां ने कहा कि हमें एक और नेक बने रहना होगा तभी हम कामयाबी हासिल हो पाएगी वरना सब बेकार रहेगा। आखिर में सज्जादा नशीन शोएब मियां ने मुल्क में अमन और शांति की दुआ की तथा लोगों से अपील किया कि सब आपस में मिलजुल कर रहें। यह क़स्बा गंगा जमुनी संस्कृति का शहर है। समापन अवसर पर मस्जिद मोअज्जिन समर अहमद, दरगाह खादिम अतीक अहमद, सैय्यद तौहीद रिज़वी, पूर्व सभासद हसरत अली, शाहिद अली मोलहे,वारिस खान, सैय्यद मोइन अल्वी, मौलाना तौक़ीर अतारी, सैय्यद इमरान किरमानी, सैय्यद शुजाउद्दीन किरमानी,अनीसुल हसन, इंजीनियर रेहान अहमद के अलावा बड़ी तादाद में नमाज़ी मौजूद थे।

## महत्वाकांक्षी कार्यक्रम तहसील संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन हर्रैया तहसील सभागार में आयोजित

●**संपूर्ण समाधान दिवस से जनता का मोह भंग हो रहा है इसका कारण कर्मचारियों द्वारा फर्जी रिपोर्ट लगाकर निस्तारण किया जा रहा है सरकारी जमीनों पर दबंगों का कब्जा उसे हटाने मे राजस्व कर्मी नहीं करते हैं कार्रवाई**

**स्वतंत्र प्रभात संवाददाता**

**बस्ती।** बस्ती जिले में जनता की समस्याओं के त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम तहसील संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन हर्रैया तहसील सभागार में जिलाधिकारी के निर्देशन में उप जिलाधिकारी सत्येन्द्र सिंह की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर पुलिस क्षेत्राधिकारी स्वर्णिमा सिंह भी उपस्थित रही।

उप जिलाधिकारी ने फरियादियों की समस्याओं को गंभीरता से सुना तथा संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्राप्त शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। अधिकारियों द्वारा कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है की गुणवत्ता पूर्ण निस्तारण किया जाए लेकिन कर्मचारी फर्जी रिपोर्ट लगाकर निस्तारण कर देते हैं दोबारा शिकायत करने पर वही रिपोर्ट की कॉपी लगाते रहते हैं जबकि जमीनी हकीकत कुछ और बयां कर रही है तहसील के जिम्मेदार अधिकारी एवं कर्मचारियों की लापरवाही से सरकारी भूमि पर दबंगों का कब्जा बना हुआ है जिसकी शिकायत और खबर चलने के बावजूद भी अधिकारियों के निगाह में कार्रवाई न करना जनता को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है पुलिस विभाग राजस्व विभाग और विकास विभाग सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार उत्पन्न हो रहा है राजस्व विभाग द्वारा शिकायतकर्ता के शिकायत पर कार्रवाई न करना हर्रैया थाना में फर्स्ट थाना अध्यक्ष और पुलिस कर्मियों द्वारा बिना रकम लिए शिकायत नहीं दर्ज किया जा रहा है दूसरी तरफ पुलिसकर्मियों द्वारा क्षेत्र में वसूली का चर्चा बना हुआ महकमा के अधिकारी अधिकारियों द्वारा पुलिस पर शिकाजा नहीं कसा जा रहा है दूसरी तरफ विकास विभाग में भ्रष्टाचार चरम पर है हर्रैया खंड विकास अधिकारी द्वारा समय पर ऑफिस पर नहीं बैठते हैं जनता के शिकायतों को ध्यान नहीं दिया जा रहा है खंड विकास अधिकारी द्वारा जनता से मिलना मुनासिब नहीं समझते हैं शिकायतों पर फर्जी रिपोर्ट लगाकर निस्तारण कर देते हैंउन्होंने कहा कि कोई भी फरियादी अपनी समस्या के समाधान की अपेक्षा से ही सरकारी कार्यालयों में आता है, इसलिए जनता की समस्याओं का समाधान करना सभी अधिकारियों की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।

उप जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिया कि जिन शिकायतों का निस्तारण मौके पर नहीं हो सका है, संबंधित विभाग के अधिकारी स्थलीय निरीक्षण कर निर्धारित समय सीमा में गुणवत्ता के साथ उनका निस्तारण सुनिश्चित करें। साथ ही जन-शिकायतों के निस्तारण में समयबद्धता और पारदर्शिता बनाए रखने पर विशेष जोर दिया।तहसील संपूर्ण समाधान दिवस में कुल 58 शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिसमें से मौके पर 07 का निस्तारण हुआ। इनमें राजस्व विभाग से संबंधित 19, पुलिस विभाग से 14, विद्युत विभाग से 07, विकास विभाग से 13 तथा अन्य 05 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए।

इस अवसर पर डीएफओ डा. शिरीन, जिला विकास अधिकारी अजय कुमार सिंह, पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी रेखा गुप्ता, जिला समाज कल्याण अधिकारी लालजी यादव, जिला सेवायोजन अधिकारी अवधेन्द्र प्रताप वर्मा, उप निदेशक कृषि अशोक कुमार गौतम, एलडीएम आर.एन. मौर्या, तहसीलदार सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

## साहब, खम्भे की जगह नीम के पेड़ से बंधा है बिजली का तार

● **हादसे का भय बना बिजली का तार**

**स्वतंत्र प्रभात संवाददाता**

**लालगंज (रायबरेली)।** तहसील सभागार में शनिवार को तहसीलदार शिवम राठौड़ अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन हुआ। उत्तरागौरी गांव निवासी विजयपाल, कृष्ण मोहन सिंह, अंजनी, शिव कुमार, अर्पित आदि ने संयुक्त रूप से शिकायती पत्र देकर गांव की बिजली लाइन दुरुस्त करने की मांग की। बताया कि हरिप्रसाद के घर के पास बिजली का केवल नीम की पेड़ से बंधा हुआ है। इससे किसी दुर्घटना होने का भय सताता रहता है। ग्रामीणों की सुविधा के लिए पोल लगाकर बिजली लाइन दुरुस्त करने की मांग की। मेरुई ग्राम प्रधान धर्मेंद्र सिंह ने सरकारी नाली पर अवैध कब्जे की शिकायत की। बताया कि कुछ लोग सरकारी नाली पर जबरन कब्जा कर रहे हैं। इससे पानी निकास प्रभावित होगा।

सातनपुर की नईम ने चक मार्ग दुरुस्त करने की मांग की। बताया कि उनके खेतों के लिए जाने वाला चकमार्ग को कुछ कास्तकारों ने काटकर अपने खेत में मिल लिया। इससे जुताई बुवाई और मड़ाई के लिए खेतों तक आना-जाना मुश्किल हो रहा है। पैमाइश करा कर चकमार्ग को दुरुस्त करने की मांग की। इस प्रकार तहसीलदार शिवम राठौड़ की अध्यक्षता में कुल 28 शिकायत दर्ज की गई। इनमें राजस्व की चार शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। इस दौरान नायब तहसीलदार ऋषभ नागर, बीडीओ गगनदीप सिंह, एसडीओ शिवम वर्मा, राजस्व निरीक्षक यादव सहित अन्य विभागों के अफसर मौजूद रहे।

### घर के सामने डीजे बजाने का विरोध करने पर युवती को घर में खींचकर पीटा

**ललितपुर।** कोतवाली थाना क्षेत्र के मोहल्ला पठापुरा में दबंगों के हौसले बुलंद हैं। घर के बाहर शोर-शराबा और गाली-गलौज करने का विरोध करने पर एक युवती को घर के अंदर खींचकर बेरहमी से पीटा गया। बीच-बचाव करने आई मां के साथ भी अभद्रता की गई। पुलिस ने एक ही परिवार के चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पठापुरा निवासी पायल अहिरवार पुत्री जगभान अहिरवार ने पुलिस को बताया कि घटना की शुरुआत 4 मार्च की शाम 4 बजे हुई, जब पड़ोस के राजकुमार अहिरवार, मुन्नी, अंजना और छाया उनके घर के सामने डीजे बजाकर गाली-गलौज कर रहे थे। उस समय विरोध करने पर आरोपियों ने पायल के साथ मारपीट की। मामला यहीं शांत नहीं हुआ, 6 मार्च की सुबह करीब 7 बजे आरोपियों ने दोबारा गाली-गलौज शुरू कर दी। पीड़िता के अनुसार, मुन्नी अहिरवार उसे घसीटते हुए अपने घर के अंदर ले गई, जहाँ सभी ने मिलकर उसे लात-घूसों से पीटा, जिससे उसके सिर और हाथ में चोटें आईं। जब पायल की मां हरकुंवर उसे बचाने पहुंचीं, तो आरोपियों ने उनके साथ भी मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी।

## पत्रकारों के समक्ष वार्ता करते महन्त रामलखनदासजी महाराज

● **पत्रकारिता के क्षेत्र में राठौर जी का योगदान अविस्मणीय : राजीव बबेले सप्पू**

**वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल राठौर जी की पुण्यतिथि उनके जीवन से जुड़े प्रसंगों को किया याद**

**अन्नपूर्णा भोजनशाला में जरुरतमंदों को कराया भोजन**

**स्वतंत्र प्रभात संवाददाता**

**ललितपुर।** वरिष्ठ पत्रकार स्व. बाबूलाल ठाकुर राठौर जी की ग्यारहवीं पुण्यतिथि के अवसर पर शनिवार को अमर शहीद पं गणेश शंकर विद्यार्थी भवन (प्रेस क्लब) में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। कार्यक्रम में जिले के पत्रकारों एवं गणमान्य लोगों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी और उनके पत्रकारिता क्षेत्र में किए गए योगदान को याद किया।

इस अवसर पर जरूरतमंदों के लिए अन्नपूर्णा भोजनशाला में भोजन कराया गया। वहीं प्रेस क्लब अध्यक्ष राजीव बबेले सप्पू ने कहा कि बाबूलाल राठौर जी ने अपने जीवनकाल में निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता की मिसाल पेश की। उन्होंने समाज की समस्याओं को प्रमुखता से उठाते हुए पत्रकारिता को जनसेवा का माध्यम बनाया। उनके आदर्श और कार्यशैली आज भी युवा पत्रकारों के लिए प्रेरणा हैं। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित पत्रकारों ने उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उन्होंने सदैव पत्रकारों के हितों के लिए कार्य किया और संगठन को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार अजित जैन भारती, उपाध्यक्ष विजय जैन कल्लू, महामंत्री अमित सोनी, चंद्रशेखर राठौर, कुंदन लाल राठौर, राजेश कुमार राठौर, सुनील जैन, अजय तोमर, शिब्बू राठौर, रमेश रायकवार, देवेश कुमार राठौर, गणेशराम रजक, चरन सिंह रामनगर, अजितेश जैन, यशपाल सिंह परमार, विकास सोनी, अनुराग बिदुआ, भगवान सिंह, पंकज रायकवार, अमित राठौर, अनि जैन आदि पत्रकार बंधु मौजूद रहे।

## एससी-एसटी आयोग के सदस्य रमेश चन्द्र 8 से झांसी-ललितपुर के दौरे पर, करेंगे निरीक्षण

**स्वतंत्र प्रभात संवाददाता**

**ललितपुर।** उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय सदस्य रमेश चन्द्र आगामी 8 से 11 मार्च 2026 तक झांसी और ललितपुर जनपद के चार दिवसीय प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान वे अनुसूचित जाति और जनजाति के व्यक्तियों की समस्याओं का अनुश्रवण करेंगे और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें करेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार रमेश चन्द्र 8 मार्च को दोपहर 12 बजे कानपुर से झांसी सर्किट हाउस पहुंचेंगे। दोपहर 1 बजे वे मुक्ता काशी कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे और तत्पश्चात क्षेत्रीय भ्रमण कर दलित समुदाय के लोगों से मुलाकात करेंगे। 9 मार्च को सुबह 11 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद के अधिकारियों के साथ एससी-एसटी वर्ग की समस्याओं के निराकरण हेतु बैठक होगी। इसके बाद वे नगर निगम मु यालय में बैठक, वृद्धाश्रमों, राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों और दलित बस्तियों का सघन निरीक्षण करेंगे। आयोग के सदस्य 10 मार्च को दोपहर 12 बजे ललितपुर पहुंचेंगे। दोपहर 12.×0 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ और दोपहर 2.×0 बजे नगर पालिका मु यालय में बैठक करेंगे। शाम 4 बजे से छात्रावासों व आश्रम पद्धति विद्यालयों का भ्रमण करेंगे और शाम 6 बजे दलित बस्तियों में जाकर जमीनी हकीकत जानेंगे। 11 मार्च को सुबह 10 बजे वे नगर पंचायत तालबेहट में जनसंवाद करेंगे और दोपहर × बजे कानपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय ललितपुर ने इस भ्रमण को लेकर विस्तृत प्रोटोकॉल जारी कर दिया है। पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए गए हैं कि वीआईपी गरिमा के अनुरूप बॉर्डर-टू-बॉर्डर सुरक्षा, ट्रैफिक व्यवस्था और पायलट सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। जिला समाज कल्याण अधिकारी और नजारत को सर्किट हाउस में ठहरने व अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए जि मेदारी सौंपी गई है।

## संक्षिप्त खबरें

### भाजपा जिलाध्यक्ष का भव्य स्वागत 2027 में योगी के नेतृत्व में सरकार बनने का दावा

**मिल्कीपुर अयोध्या** भारतीय जनता पार्टी के नव नियुक्त जिलाध्यक्ष राधेश्याम त्यागी का नगर पंचायत कुमारगंज में स्वागत समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन प्रबुद्ध प्रकोष्ठ के संयोजक एवं भाजपा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष चंद्रबली सिंह के नेतृत्व में किया गया। इस अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण और ढोल-नगाड़ों के साथ जिलाध्यक्ष का जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष राधेश्याम त्यागी ने कहा कि हमें भारत माता की जय के संकल्प के साथ आगे बढ़ना है। हमारे पूर्वजों ने भारत माता की जय कहते हुए अपने प्राणों की आहुति दी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है और देश उसी दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। अयोध्या में भगवान श्रीराम का भव्य मंदिर बन चुका है और अब देश के विकास की नई शुरुआत अयोध्या से हो रही है। भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो हर वर्ग और समाज को साथ लेकर चलती है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने एक सामान्य कार्यकर्ता को, जो अनुसूचित जाति समाज से आता है, अयोध्या का जिलाध्यक्ष बनाकर सामाजिक समरसता का उदाहरण प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग जाति के नाम पर समाज और देश को बांटने की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन अयोध्या में पीडीए नहीं बल्कि समता का राज चलेगा। भगवान राम ने भी समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलने का संदेश दिया था। उन्होंने निषादराज को अपना मित्र बनाया और शबरी के झूठे बेर खाकर सामाजिक समरसता का संदेश दिया। वहीं कार्यक्रम के आयोजक चंद्रबली सिंह ने कहा कि मिल्कीपुर के राधेश्याम त्यागी को भाजपा ने जिलाध्यक्ष बनाकर क्षेत्र का सम्मान बढ़ाया है। उनके नेतृत्व में हम सभी कार्यकर्ता संगठन को मजबूत करेंगे और समाज के लिए काम करेंगे। इस दौरान शिवनगर में अजय विक्रम सिंह के नेतृत्व में ढोल-नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया। कुमारगंज हनुमानगढ़ी पर दिनेश कौशल, बंवा मोड़ पर विजय कुमार उपाध्याय तथा खंडासा मोड़ पर सभासद रवि सिंह के नेतृत्व में भी स्वागत किया गया। कार्यक्रम में कुमारगंज मंडल अध्यक्ष अमरेंद्र मौर्य, बलवंत सिंह, सरबजीत सिंह, अंगद सिंह, सुरेश सिंह, भानु गोस्वामी, अरुण गोस्वामी सहित कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे।

### अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर संगोष्ठी का हुआ आयोजन

**सिद्धार्थनगर।** अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर शनिवार को उसका ब्लॉक क्षेत्र के देवलहवा ग्रांट में नाबार्ड के तत्वावधान में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर महिलाओं के उद्यमिता विकास, आत्मनिर्भरता और सामाजिक भागीदारी पर विस्तृत चर्चा की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक नागराजन ने कहा की जब महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त होंगी और उद्यमिता के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगी, तभी गांव और देश सच्चे अर्थों में समृद्ध बन पाएंगे। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के लिए कई महत्वाकांक्षी योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिनमें 40 प्रतिशत तक सब्सिडी का प्रावधान है। महिलाएं इन योजनाओं का लाभ उठाकर स्वरोजगार शुरू कर सकती हैं और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत बना सकती हैं।

नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक हिमांशु त्रिपाठी ने कहा की अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक योगदान देने का अवसर है। कार्यक्रम के आयोजक श्रीधर पांडेय ने कहा कि समाज में महिलाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऐसे कार्यक्रम समय-समय पर आयोजित किए जाते रहेंगे। उन्होंने सभी अतिथियों और प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया। इस दौरान समाजसेवी सरिता पांडेय, राणा प्रताप सिंह, अविनाश कुमार, आजाद शुक्ला, डी.एन. शुक्ला , मनोज कुमार आदि रहे।

## केवल वादे या वास्तविक विकास! जिले के दुल्लभछड़ा में केंद्रीय विद्यालय और मॉडल डिग्री कॉलेज अभी भी अधर में

● शिक्षा परियोजनाएँ किसी भी क्षेत्र के विकास की नींव होती हैं, आज भी इन योजनाओं से वंचित!

जिले के संबंधित विभाग के अधिकारी मौन।

क्षेत्र के लोगों ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

**श्रीभूमि:** शिक्षा परियोजनाएँ किसी भी क्षेत्र के विकास की नींव होती हैं। लेकिन असम के श्रीभूमि जिले के दुल्लभछड़ा क्षेत्र में इन योजनाओं की हालत आज भी निराशाजनक है। संबंधित विभाग के अधिकारी मौन हैं, जबकि क्षेत्रवासियों ने लोकप्रिय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया। श्रीभूमि जिले के रामकृष्णनगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत दुल्लभछड़ा में मॉडल डिग्री कॉलेज बनाने की घोषणा 30 मई 2023 को की गई थी। उस समय कहा गया कि लगभग 75 बीघा जमीन पूर्ति विभाग को सौंप दी गई है और 35 करोड़ रुपये के बजट की चर्चा भी हुई थी। स्थानीय लोकप्रिय विधायक विजय मालाकार ने इस क्षेत्र को 'एजुकेशनल हब' बनाने का आश्वासन दिया था और केंद्रीय विद्यालय स्थापित करने की योजना भी साझा की थी। लेकिन तीन साल गुजरने के बाद भी कोई स्पष्ट प्रगति नहीं दिखी। इससे क्षेत्रवासियों में निराशा और असंतोष बढ़ रहा है। जनप्रतिनिधियों और विभागीय अधिकारियों की चुप्पी भी कई सवाल खड़े कर रही है। 'जिले के सभी क्षेत्र में विकास का काम लगातार चल रहा है' जिले में अधिकांश जगहों पर सुधार और नई सुविधाओं की स्थापना हो रही है। 'लेकिन विकास की रोशनी अभी भी दुल्लभछड़ा तक नहीं पहुँची है' इसका मतलब है कि दुल्लभछड़ा क्षेत्र अभी भी पिछड़ा हुआ है और वहां विकास कार्यों की कमी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कांग्रेस शासनकाल में उपेक्षा के बाद भी वर्तमान भाजपा सरकार में कोई बड़ा बदलाव दिखाई नहीं देता।

आज भी दुल्लभछड़ा के छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए दूर-दराज़ के शहरों में जाना पड़ता है, जिससे परिवारों पर आर्थिक और सामाजिक बोझ बढ़ता है। जबकि राज्य में मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा के नेतृत्व में कई जगह शिक्षा क्षेत्र में विकास हुआ है, दुल्लभछड़ा में वह गति दिखाई नहीं देती। इसलिए स्थानीय नागरिक और छात्र-छात्राएँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य सरकार से आग्रह करते हैं कि इस परियोजना की जल्द जांच कर प्रभावी कदम उठाए जाएँ। अब सवाल यही है: क्या दुल्लभछड़ा का 'एजुकेशनल हब' सिर्फ़ एक राजनीतिक वादा बनकर रह जाएगा, या सच में जमीन पर उतरेगा! शिक्षा किसी भी क्षेत्र के समग्र विकास की बुनियाद होती है। इसलिए जिले के दुल्लभछड़ा में लोगों के हित और छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा संस्थाओं की स्थापना के लिए जरूरी केंद्रीय विद्यालय और मॉडल डिग्री कॉलेज की स्थापना अब केवल मांग नहीं, बल्कि समय की आवश्यकता बन गई है।

## रंगपंचमी पर परशुराम मंदिर में होगा ब्राह्मण समाज का होली मिलन समारोह

**महरौनी।** ब्राह्मण समाजोत्थान सेवा संस्थान के तत्वाधान में रंगपंचमी के पावन अवसर पर ब्राह्मण महामंडल महरौनी विधानसभा क्षेत्र का होली मिलन समारोह 8 मार्च 2026, रविवार को दोपहर 2 बजे आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम कस्बा महरौनी के मड़ावरा रोड स्थित पंडा कॉलोनी में भगवान परशुराम मंदिर प्रांगण में संपन्न होगा। कार्यक्रम में महरौनी विधानसभा क्षेत्र के सभी ग्रामों के स माननीय विप्र बंधुओं के साथ-साथ नवनिर्वाचित समिति के संरक्षक एवं पदाधिकारीगण की उपस्थिति रहेगी। आयोजकों ने सभी विप्र बंधुओं से कार्यक्रम में अनिवार्य रूप से उपस्थित होकर इसे सफल बनाने की अपील की है। संगठन अध्यक्ष रामविलास कटारे ने जानकारी देते हुए बताया कि यह होली मिलन समारोह समाज में आपसी सौहार्द, एकता और भाईचारे को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने क्षेत्र के सभी विप्र बंधुओं से अधिक से अधिक स या में उपस्थित होकर कार्यक्रम को सफल बनाने का आग्रह किया है।

## असम के उत्तर करीमगंज में कांग्रेस उम्मीदवार की घोषणा पर बीजेपी टिकट प्रत्याशी मुन्नी छेत्री की प्रतिक्रिया

● 'उम्मीदवार जकरिया अहमद पन्ना उत्तर करिमगंज में कोई बड़ा फैक्टर नहीं हैं। क्षेत्र की जनता विकास को प्राथमिकता देते हुए लोक विकास के मार्ग पर ही अपना वोट देगी: मुन्नी छेत्री।

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

**श्रीभूमि:** असम श्रीभूमि जिले के उत्तर करीमगंज: चुनाव के माहौल में पूरे असम राज्य में राजनीतिक उत्साह लगातार बढ़ रहा है। बराक घाटी के 13 सीटों को लेकर अब चाय की दुकान से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह जोरदार राजनीतिक चर्चा चल रही है। इसी बीच असम के उत्तर करीमगंज क्षेत्र में कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार के रूप में ज़कारिया अहमद (पान्ना) का नाम घोषित किया है, जिससे राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा शुरू हो गई है।

हालांकि अब तक शासक दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने अपनी उम्मीदवार सूची घोषित नहीं की है। लेकिन इसी परिस्थिति में बीजेपी की टिकट प्रत्याशी महिला नेता मुन्नी छेत्री ने उत्तर करीमगंज की राजनीतिक स्थिति पर पहली प्रतिक्रिया व्यक्त की है। मुन्नी छेत्री कहती हैं कि बीजेपी सरकार के विकास के मार्ग के सामने कांग्रेस के उम्मीदवार ज़कारिया अहमद कोई पहलू नहीं हैं। उनका दावा है कि अब के मतदाता पहले से कहीं अधिक जागरूक हैं और वे अब कांग्रेस की कथित 'मुस्लिम मित्रता' या धर्म आधारित राजनीति से प्रभावित नहीं होंगे। उन्होंने आगे कहा, पहले विलुप्त हो चुके बदरपुर क्षेत्र में वर्षों से लोग कांग्रेस प्रतिनिधियों से जुड़े रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव के समय धर्म का सहारा लेकर अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय वादे और आश्वासन के नाम पर वोट प्राप्त किया गया, लेकिन चुनाव के बाद जनता की समस्याओं को हल करने के लिए कोई विशेष पहल नहीं की गई। मुन्नी क्षेत्री का दावा है कि अल्पसंख्यक मुस्लिम मतदाताओं में सत्ताधारी दल के खिलाफ डर पैदा करने का प्रयास किया गया। हालांकि, उनके अनुसार, जनता अब इन सभी चालों को समझ चुकी है और इस बार आसानी से जनता ठगी नहीं खाएगी। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस उम्मीदवार की घोषणा के बाद से उत्तर करीमगंज की राजनीतिक स्थिति काफी गर्म हो गई है। राजनीतिक पर्यवेक्षकों के अनुसार, आगामी चुनाव में यह सीट एक प्रमुख चर्चित संघर्ष का क्षेत्र बन सकती है।

## सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु में राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर का हुआ शुभारम्भ

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

**सिद्धार्थनगर,** सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु परिसर में संचालित राष्ट्रीय सेवा योजना की तीन इकाई,भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेई इकाई, महारानी अहिल्या बाई होलकर इकाई, एवं नेताजी सुभाष चन्द्र बोस इकाई, के सप्त दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन कुलपति प्रो कविता शाह के निर्देशन में प्रारम्भ हुआ। सप्त दिवसीय विशेष शिविर के प्रथम दिवस का प्रारम्भ शिविर के उद्घाटन सत्र को प्रो नीता यादव अधिष्ठाता छात्र कल्याण की अध्यक्षता में हुआ । कार्यक्रम का शुभारंभ सरस्वती प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर किया गया। उन्होंने अपने अध्यक्षीय वक्तव्य में कहा कि स्वयंसेवक- स्वयंसेविकाओं को बेहतर चरित्र निर्माण के साथ- साथ एक सभ्य समाज के भी निर्माण करने की आवश्यकता है।

कार्यक्रम के प्रथम बौद्धिक सत्र में मुख्य वक्ता के रुप में डॉ मनीषा वाजपेई, सहायक आचार्य, भौतिक विज्ञान विभाग ने 'सभ्य समाज के निर्माण में राष्ट्रीय सेवा योजना की भूमिका' विषय पर कहा कि मानव जीवन का बेहतर निर्माण आदर्शों एवं मानव मूल्यों से ओतप्रोत होता है। इस तरह के जीवन निर्माण में स्वयंसेवक स्वयंसेविकाओं की सक्रियता बहुत अधिक प्रासंगिक होती है।मानवता को जीवंत रखने हेतु राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़े लोग अपने सम्पूर्ण जीवन को भारत माता को समर्पित कर देते हैं। प्रथम दिवस के द्वितीय बौद्धिक सत्र में वक्ता के रुप में डॉ हरेंद्र कुमार शर्मा ने ' मानव मूल्य निर्माण में राष्ट्रीय सेवा योजना का योगदान' विषय पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना का योगदान मानव मूल्य निर्माण में बहुत ही अधिक योगदान प्रदान करता है। राष्ट्रीय सेवा योजना भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेई इकाई के कार्यक्रम अधिकारी डॉ यशवन्त यादव, महारानी अहिल्या बाई होलकर इकाई की कार्यक्रम अधिकारी डॉ रक्षा एवं नेताजी सुभाष चन्द्र बोस इकाई की कार्यक्रम अधिकारी डॉ सरिता सिंह के मार्गदर्शन एवं निर्देशन में संपूर्ण कार्यक्रम संचालित हुआ। सांस्कृतिक संध्या में स्वयंसेवक-स्वयंसेविकाओं ने मानव मूल्य से जुड़े गीत संगीत एवं अन्य विधा से उपस्थित सभी लोगों को आनंदित होने का अवसर प्रदान किया। उद्घाटन सत्र का संचालन डॉ यशवन्त यादव, स्वागत डॉ रक्षा एवं आभार डॉ सरिता सिंह द्वारा किया गया।

## मड़ावरा में बार संघ के चुनाव संपन्न, कपिल दुबे बनें अध्यक्ष

**मड़ावरा।** ललितपुर के मड़ावरा में शनिवार को बार संघ तहसील का चुनाव संपन्न हुआ। पूरे मतदान में 41 मतदाताओं के सापेक्ष ×5 ने अपने मत का उपयोग किया। जिसमें कपिल दुबे ने अध्यक्ष पद के लिए जीत हासिल की। शनिवार की सुबह 11 बजे से पुलिस सुरक्षा के बीच तहसील अध्यक्ष पद के लिए पूरी पारदर्शिता के साथ मतदान शुरू हुआ। अध्यक्ष पद के लिए दो प्रत्याशी मैदान में थे। इस लिए चुनाव काफी दिलचस्पी था। मतदान शुरू होते ही काफी रुचि देखी गई। कम समय में ही 41 मतदाताओं में से ×5 ने अपने मत का उपयोग किया। मतदान प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात मत पेटिका को खोला गया। जिसमें अध्यक्ष पद के उ मीदवार एड. कपिल दुबे को 20 मत प्राप्त हुए, जबकि प्रतिद्वंदी एड. रणवीर सिंह को 15 वोट मिले। इस प्रकार एड. कपिल दुबे ने 5 वोटों से जीत हासिल कर ली। वहीं, उपाध्यक्ष पद के लिए प्रमोद कुमार चतुर्वेदी, सचिव/मंत्री पद पर जगभान सिंह, कोषाध्यक्ष पद पर रमेश चन्द्र पाल, संगठन सचिव चिंतामन वर्मा समेत कार्यकारिणी के 5 सदस्य निर्विरोध पहले ही चुने गए थे।

## पत्रकारों पर बढ़ते हमलों को लेकर द जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने सौंपा ज्ञापन, पत्रकार सुरक्षा अधिनियम लागू करने की मांग

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

**गोण्डा।** उत्तर प्रदेश में पत्रकारों पर लगातार बढ़ रहे हमलों और दुर्व्यवहार की घटनाओं को लेकर द जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने शनिवार को कर्नलगंज तहसील में मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन उपजिलाधिकारी नेहा मिश्रा को सौंपा। संगठन ने ज्ञापन के माध्यम से प्रदेश में पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और पत्रकार सुरक्षा अधिनियम जल्द लागू करने की मांग की है।ज्ञापन में संगठन ने प्रदेश में पत्रकारों के साथ हो रही हिंसक घटनाओं पर गहरी चिंता व्यक्त की। विशेष रूप से गोरखपुर जिले के बांसगांव क्षेत्र में 27 फरवरी को पत्रकार एवं अधिवक्ता अग्निवेश सिंह की दिनदहाड़े पीट-पीटकर की गई हत्या का जिक्र किया गया। बताया गया कि नाली विवाद के दौरान दबंगों ने लाठी-डंडों और धारदार हथियारों से हमला कर उनकी निर्मम हत्या कर दी, जबकि इस हमले में उनके भाई और पिता भी घायल हो गए। मामले में पुलिस ने नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। संगठन ने मांग की है कि इस मामले की निष्पक्ष और त्वरित जांच कर दोषियों को कठोर से कठोर सजा दी जाए। साथ ही पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता तथा परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की भी मांग की गई है। इसके अलावा वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ धाम में रंगभरी एकादशी के दौरान कवरेज कर रही एक महिला पत्रकार के साथ कथित दुर्व्यवहार की घटना का भी उल्लेख किया गया। आरोप है कि एसीपी सुरक्षा अंजनी कुमार राय ने महिला पत्रकार के साथ अनुचित व्यवहार करते हुए उसे धक्का दिया तथा उसके सहयोगी को थप्पड़ मार दिया। इस घटना को लेकर पत्रकार संगठनों में आक्रोश है। द जर्नलिस्ट एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में पहुंचे पत्रकारों ने कहा कि इस प्रकार की घटनाएं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर सीधा हमला हैं। यदि पत्रकार सुरक्षित नहीं होंगे तो स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता संभव नहीं हो पाएगी। इसलिए प्रदेश सरकार को पत्रकारों की सुरक्षा के लिए ठोस कानून बनाना चाहिए। इस मौके पर एमडी मौर्य, पवनदेव सिंह, प्रवीण श्रीवास्तव, अभय प्रताप सिंह, शिवकुमार पाण्डेय, अवधराज गोस्वामी, अमरेश प्रजापति, रविकांत मिश्र सहित कई पत्रकार मौजूद रहे। उपजिलाधिकारी नेहा मिश्रा ने ज्ञापन प्राप्त करते हुऐ उच्चाधिकारियों तक भेजने का आश्वासन दिया है।

## डीएम की अध्यक्षता में तहसील बलरामपुर में 'सम्पूर्ण समाधान दिवस' संपन्न

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

**बलरामपुर।** जिलाधिकारी विपिन कुमार जैन की अध्यक्षता में शनिवार को तहसील बलरामपुर में 'सम्पूर्ण समाधान दिवस' का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने जनमानस की समस्याओं को गंभीरता से सुना और उनके समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक विकास कुमार भी मौजूद रहे। जिलाधिकारी ने कहा कि शिकायतों के निस्तारण में किसी प्रकार की लापरवाही या ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि शिकायतों का समाधान तय समय सीमा के भीतर हो और वह गुणवत्तापूर्ण व शिकायतकर्ता की संतुष्टि के अनुरूप होना चाहिए।

**संयुक्त टीम द्वारा कार्रवाई**

भूमि विवाद एवं कानून-व्यवस्था से जुड़े मामलों पर सख्त रुख अपनाते हुए जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीमें मौके पर पहुंचकर निष्पक्ष जांच करें और विवादों का समाधान सुनिश्चित करें।

**संवेदनशील ग्रामों में चौपाल**

जिलाधिकारी ने उन ग्रामों को चिन्हित करने के निर्देश दिए, जहां भूमि विवाद के मामले अधिक हैं। ऐसे गांवों में राजस्व व पुलिस विभाग द्वारा विशेष चौपाल आयोजित कर मौके पर ही मामलों का निपटारा करने को कहा गया है।

**समीक्षा एवं त्वरित निस्तारण**

समाधान दिवस के अंत में जिलाधिकारी ने प्राप्त सभी प्रार्थना पत्रों की समीक्षा की। कार्यक्रम के दौरान कई शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया, जबकि शेष शिकायतों को संबंधित विभागों के अधिकारियों को सौंपते हुए निर्देश दिया गया कि वे स्वयं स्थल निरीक्षण कर निर्धारित समय सीमा के भीतर समाधान सुनिश्चित करें। इस दौरान एसडीएम बलरामपुर, सीओ सिटी, जिला पंचायत राज अधिकारी सहित अन्य संबंधित अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।

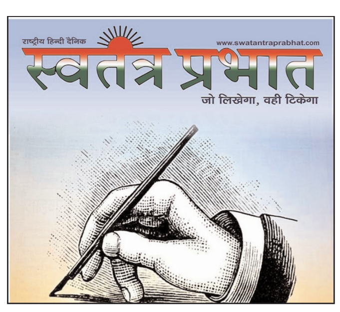


## मोकलपुर की क्षतिग्रस्त पुलिया को लेकर युवा कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

**मनकापुर गोण्डा:** विकास खण्ड बभनजोत स्थित बस्ती डोमा ग्राम पंचायत के मजरा मोकलपुर के पास क्षतिग्रस्त पुलिया को लेकर शनिवार को उत्तर प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव व पीसीसी सदस्य अभिषेक तिवारी नीरज के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में क्षेत्रीय लोगों व कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना-प्रदर्शन किया और पुलिया के शीघ्र निर्माण की मांग की।इस धरने को समर्थन देने के लिए पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि मोहन लाल यादव तथा जिला पंचायत सदस्य अमर यादव और बसंत यादव भी मौके पर पहुंचे और क्षेत्रीय जनता की समस्या को गंभीर बताते हुए प्रशासन से तत्काल समाधान की मांग की।उन्होंने कहा कि इस मार्ग पर स्थित क्षतिग्रस्त पुलिया से आये दिन वाहन सहित राहगीर गिरकर चोटिल होते रहते है और इसी मार्ग से सुबह शाम स्कूली बच्चो को आना जाना लगा रहता है।प्रदर्शन के बाद मौके पर पहुंचे सहायक अभियंता प्रिंस कुमार मल्ल ने लिखित आश्वासन दिया कि अप्रैल माह से पहले ही पुलिया के निर्माण कार्य को शुरू कर दिया जाएगा तथा फिलहाल आवागमन को सुचारु रखने के लिए अस्थायी वैकल्पिक व्यवस्था तुरंत कराई जा रही है, ताकि क्षेत्र की जनता को परेशानी न हो।

नेतृत्व कर रहे अभिषेक तिवारी नीरज ने कहा कि क्षेत्र की जनता की समस्याओं को लेकर संघर्ष जारी रहेगा और जब तक पुलिया का निर्माण कार्य शुरू नहीं होता, तब तक आवाज उठती रहेगी।

इस मौके पर संदीप सक्सेना पवन सिंह सचिन कनौजिया सुरेंद्र ओमकार यादव वालीउल्लाह रवि पांडेय, चित्रांश मौर्य, अखिलेश कुमार पाठक, नरेंद्र पाठक, अंकित गुप्ता, ध्रुव चंद पाठक, अमर पाठक, दीपक, विजय कुमार कनौजिया, पहलाद शर्मा, इंदर कुमार विजय कुमार, विजय वर्मा, आदित्य वर्मा बबलू गौतम, सूरज साहू सुरेंद्र वर्मा सहित आदि लोग उपस्थित रहे।

## जनऊपुर में ब्राह्मण स्वयंसेवक संघ का भव्य होली मिलन समारोह, 51 विप्र बंधु और 50 से अधिक प्रधान हुए सम्मानित

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

**बलिया।** ब्राह्मण स्वयंसेवक संघ, जनपद बलिया के तत्वाधान में रतसर क्षेत्र के जनऊपुर गांव में इंजीनियर तारकेश्वर पाण्डेय के आवास पर भव्य होली मिलन एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान श्री परशुराम के चित्र पर माल्यार्पण, पुष्प अर्पित करने और आरती के साथ हुई। इस अवसर पर प्रख्यात कथा वाचक आचार्य रामकुमार शुक्ला एवं आचार्य वागीश शुक्ला के साथ गीतकार पारस नादान और उनके सहयोगियों द्वारा पारंपरिक होली गीतों की प्रस्तुति दी गई, जिसका उपस्थित श्रोताओं ने भरपूर आनंद लिया। कार्यक्रम के दौरान संगठन की ओर से 51 विप्र बंधुओं तथा 50 से अधिक प्रधान, पूर्व प्रधान और गणमान्य व्यक्तियों को अंगवस्त्र व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बलिया के सांसद सनातन पाण्डेय ने सभी को होली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि होली समरसता, प्रेम और आपसी भाईचारे का पर्व है, जो समाज में सद्भाव और एकता को मजबूत करता है। कार्यक्रम का संचालन करते हुए संगठन के प्रदेश महासचिव राजेश मिश्र ने संगठन के उद्देश्य और कार्यों से लोगों को अवगत कराते हुए समाज में आपसी सद्भाव बढ़ाने की अपील की।

इस अवसर पर पूर्व विधायक भगवान पाठक, पूर्व चेयरमैन केसरी नंदन त्रिपाठी, भूमि विकास बैंक के अध्यक्ष परमेश्वर गिरी, दया शंकर तिवारी, बीएसएस प्रदेश सचिव ओमप्रकाश पाण्डेय, जिला प्रभारी विष्णु मिश्र, संरक्षक अरुण ओझा, धनंजय पाण्डेय, राजू दुबे, प्रिंस पांडेय, सरोज दुबे, मनीष दुबे, सत्येंद्र पांडेय, अखिलेश मिश्रा,

बृजमोहन मिश्रा, अमरनाथ मिश्र, प्रेम नारायण पांडेय, राजेंद्र प्रसाद पांडेय, अभिषेक पांडेय, प्रकाश चौबे, बंटी पांडेय सहित ब्राह्मण स्वयंसेवक संघ के कई पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में ग्रामवासी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में आयोजक इंजीनियर तारकेश्वर पाण्डेय ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। समारोह की अध्यक्षता संगठन के जिलाध्यक्ष संजय मिश्रा ने की।

## ख़जनी क्षेत्र खुंटभार में निकली भव्य कलश यात्रा, श्रीमद्भागवत कथा के साथ गूंजा भक्ति का माहौल

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

**ख़जनी:** गोरखपुर खजनी क्षेत्र के ग्राम पंचायत खुंटभार स्थित बरीबंदुआरी गांव में आयोजित सप्ताह भर चलने वाली श्रीमद्भागवत कथा के प्रथम दिन भव्य कलश यात्रा निकाली गई। गांव की सैकड़ों महिलाओं ने सिर पर कलश रखकर श्रद्धा और भक्ति के साथ शोभायात्रा में भाग लिया। पूरे गांव में जयघोष, भजन-कीर्तन और धार्मिक नारों से वातावरण पूरी तरह भक्तिमय हो गया। कलश यात्रा के बाद कथा पंडाल में विधिवत पूजा-अर्चना के साथ श्रीमद्भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। कथा वाचक मानस महाराज, वृंदावन ने उपस्थित श्रद्धालुओं को भागवत कथा के महत्व के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि श्रीमद्भागवत कथा मोक्ष, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की वैतरणी है। इसके श्रवण मात्र से मनुष्य के भीतर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और भगवान के चरणों में भक्ति का भाव जागृत होता है।

कथा प्रसंग के दौरान महाराज ने राजा परीक्षित और कलियुग के प्रारंभ की कथा सुनाते हुए बताया कि राजा परीक्षित ने कलियुग को जुआ, मदिरालय, बूचड़खाना और वेश्यालय जैसे चार स्थानों पर रहने का आदेश दिया था। जब कलियुग ने इन स्थानों को कम बताते हुए अन्य स्थान की मांग की तो राजा परीक्षित ने उसे अन्याय से अर्जित धन और सोने में निवास करने की अनुमति दे दी। कलियुग ने छलपूर्वक राजा के स्वर्ण जटित मुकुट में ही अपना स्थान बना लिया, जिससे कलियुग का प्रभाव प्रारंभ हुआ। उन्होंने आगे बताया कि जब श्रृंगी ऋषि के श्राप से राजा परीक्षित को सात दिन में तक्षक नाग के डसने से मृत्यु होने का समाचार मिला तो उन्होंने मोक्ष प्राप्ति का उपाय जानने के लिए ऋषि-मुनियों से मार्गदर्शन मांगा। तब उन्हें सात दिन में श्रीमद्भागवत कथा श्रवण का उपाय बताया गया। इसके बाद महर्षि शुकदेव ने राजा परीक्षित को सप्ताह भर श्रीमद्भागवत कथा सुनाई, जिससे उन्हें वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। कार्यक्रम में मुख्य यजमान के रूप में विशिष्ट नारायण त्रिपाठी और भानमती देवी ने विधि-विधान से पूजा-अर्चना की। इस अवसर पर क्षेत्र के अनेक श्रद्धालु, ग्रामीण और भक्तगण बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। पूरे गांव में कथा को लेकर उत्साह और श्रद्धा का माहौल बना हुआ है। आयोजकों ने बताया कि सप्ताह भर प्रतिदिन श्रीमद्भागवत कथा का रसपान श्रद्धालुओं को कराया जाएगा।